राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शुक्रवार • 27 दिसम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

जहां मूर्ख नहीं पूजे जाते, जहां अन्न की सुरक्षा की जाती है और जहां परिवार में कलह नहीं होती, वहां लक्ष्मी निवास करती हैं।
-अथर्ववेद

दिल्ली की नौटंकी

राजधानी दिल्ली की राजनीति निंदा, आलोचना, समीक्षा, प्रशंसा आदि की हदों से पार हो गई है। जब आपके सामने हो रहा नाटक आपकी कल्पनाओं को भी पीछे छोड़ दे तो आप कोई टिप्पणी करने की बजाय हैरत से सिर्फ तमाशा देखते हैं। दिल्ली में इस समय ऐसा ही तमाशा चल रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, जो हमेशा अपनी वाणी-व्यवहार के कारण सुर्खियों में बने रहने के मनोरोग की हद तक आदी हो गए हैं, इस समय दिल्ली में उन भावी योजनाओं को लेकर जो तब लागू की जाएंगी जब वह एक बार फिर चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो जाएंगे। उनकी एक योजना है महिला सम्मान योजना जिसके तहत दिल्ली की प्रत्येक वयस्क मतदाता

महिला को प्रति माह 2100 रुपये दिए जाएंगे और दूसरी संजीवनी योजना है जिसके अंतर्गत 60 साल से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए वे अपनी पार्टी के साथ पंजीकरण अभियान चला रहे हैं। इसमें केजरीवाल को कुछ भी अटपटा नहीं दिखाई देता कि जो पंजीकरण किसी भी तर्क के अनुसार मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो जाने के बाद कराया जाना था, वह मुख्यमंत्री बनने के लिए कराया जा रहा है। जाहिर है विरोधी दल इस योजना को अनैतिक और फ्रॉड बता रहे हैं लेकिन असल तमाशा यह है कि दिल्ली सरकार के जिन दो विभागों से ये योजनाएं संबंधित हैं, उन दोनों ने अधिसूचना जारी करके दिल्ली की जनता को सचेत किया है कि ये योजनाएं उनके विभागों में अधिसूचित नहीं हैं। इसलिए दिल्ली की जनता इनसे सावधान रहे। दूसरी ओर, भाजपा के नेता प्रवेश वर्मा अपने घर पर निर्धन महिलाओं, जो उनके क्षेत्र की मतदाता हैं, को 1100 रुपये की नकद सहायता राशि उपलब्ध करा रहे हैं। उनका कहना है कि यह वह राशि अपने स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। कोई कानून गरीब महिलाओं की मदद करने पर रोक नहीं लगाता। इस पर मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि वर्मा के घर करोड़ों की नकदी मौजूद है और ईडी, सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा देश इस नौटंकी को देख रहा है, कोई हंस रहा है, कोई क्षुब्ध हो रहा है, लेकिन इस नौटंकी के किसी भी पात्र को अपने गिरेबां में झांकने की फुर्सत नहीं है। यह बेहद दुखद स्थिति है जिससे निकलने के उपाय खोजे जाने चाहिए।

कामकाज का बेहतर मूल्यांकन

देश के पढ़े-लिखे लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनुरोध किया है कि वे आजादी के सात दशकों में विभिन्न सरकारों के कामकाज का मूल्यांकन करें। सुशासन को भारतीय जनता पार्टी की पहचान बताते हुए कहा कि निश्चित मापदंडों में मूल्यांकन से पता चलेगा कि हम जनसामान्य के प्रति कितने समर्पित हैं। मोदी ने कहा, जहां कांग्रेस है, वहां सुशासन हो ही नहीं सकता। जिन राज्यों में एक ही परिवार की सरकारें या मिली-जुली सरकारें रही हैं और जहां भाजपा की सरकार रही है, वहां क्या काम कैसे हुए, का अध्ययन करने को कहा। मप्र के खजुराहो में केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखने के मौके पर उन्होंने यह बात की। शासन का मतलब मोदी ने बताया कि

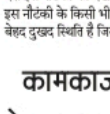

नागरिकों को अपने हकों के लिए सरकार के आगे हाथ न फैलाना पड़े, सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। कांग्रेस पर सीधा प्रहार करते हुए मोदी ने कहा कि वह राज को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड को शर्मनाक बताते हुए शासन और सुशासन को एक-दूसरे का विरोधी बताया। इस परियोजना के तहत मप्र के दस जिलों के 44 लाख तथा उप्र के 21 लाख रहवासियों को पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। किसानों को भरपूर सिंचाई के अलावा औद्योगिक उपयोग के लिए भी जल मिलेगा। बुंदेलखंड के सूखा क्षेत्र के भूजल में इससे सुधार हो सका तो यह वहां के निवासियों के लिए जीवनदायी साबित हो सकेगी जो दशकों से जल संकट से जूझने को मजबूर होकर पलायन करते रहे हैं। मगर यहां के विकास पर लगे रोड़ों के लिए केवल विपक्ष पर आरोप मढ़ना उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपने काम और जिम्मेदारियों का प्रचार करने से बेहतर है कि अपनी जिम्मेदारियों को जमीनी स्तर पर कारगर बनाया जाए। वरना पांच सालों तक जनता मूक रहते हुए तो आकलन करती ही रहती है। अंततः तो चुनाव जनता जनार्दन के हाथ ही होता है। वह असंतुष्ट होगी तो कितनी भी बयानबाजी या छाती ठोंकने के बावजूद गद्दीनशीं नहीं होने देगी। सरकारी कामकाज का मूल्यांकन बेशक, केवल शिक्षित समुदाय ही नहीं करता है, बल्कि देश का हर नागरिक अपने-अपने तईं तीक्ष्ण नजरिए से सत्ता को परखने की जिम्मेदारी भरपूर निभाता है।

सहज ऋण/डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

बदल गई जीवनशैली

आम आदमी की वित्तदायी संस्थाओं तक सहज पहुंच और संस्थागत और गैर-संस्थागत वित्तदायी संस्थाओं द्वारा आसानी से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का परिणाम है कि देश में गांवों में रहन-सहन में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। आज कोई भी व्यक्ति साधन और सुविधाओं की ओर देखता है, और उन सुविधाओं को पाने के लिए कर्ज भी लेना पड़े तो व्यक्ति दो बार सोचता नहीं है। यही समय और सोच का बदलाव है।

भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की व्यापक वार्षिक माड्यूलर रिपोर्ट के अनुसार शहरों की तुलना में गांवों में ऋण लेने वाले अधिक होते जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार गांवों में प्रति एक लाख पर 18,714 लोगों ने किसी न किसी तरह का कर्ज लिया है वहीं शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा 17,442 है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब संस्थागत ऋणों की उपलब्धता सहज हो गई है पर गैर-संस्थागत ऋण प्रदाताओं ने भी तेजी से पांव पसारे हैं। हालांकि चिंतनीय यह है कि गैर-संस्थागत ऋण प्रदाताओं में कहीं न कहीं पुराने साहूकारों की झलक दिखाई देती है। दूसरी चिंता का कारण यह है कि संस्थागत ऋण में भी ऋणों की ब्याज दर कहीं अधिक है, और उससे भी ज्यादा गंभीर यह है कि संस्थागत हो या गैर-संस्थागत ऋण प्रदाता ऋणी की एक किश्त भी समय पर जमा नहीं होती है, तो दंडनीय ब्याज, वसूली के नाम पर संपर्क और पताचार आदि का खर्चा और इसी तरह के अन्य छुपे चार्जेज ऋणी की कमर तोड़ने में काफी हैं।

सहज ऋण उपलब्धता के साइड इफेक्ट्स भी हैं। पहला तो यह कि कुछ इस तरह के ऋण होते हैं, जिन्हें होड़ा होड़ी में लिया जाता है, और उनका सीधा असर कर्ज के मकड़जाल में फंसने की तरह हो जाता है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ऋण लेने में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। शहरों की तरह गांव भी आधुनिकतम सुख-सुविधाओं से संपन्न हों इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। विकास की गंगा भी सभी तरफ समान रूप से बहनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते कर्ज के पीछे सबसे चिंतनीय बात यह है कि कहीं ग्रामीण कर्जों के मकड़जाल में फंस कर कुछ पाने की जगह खो अधिक देते हैं। इसकी आशंकाएं जब-तब दिखती रहती हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि संस्थागत ऋण यानी बैंक प्रदत्त ऋण हों या गैर-संस्थागत ऋणदाता, परेशानी इनकी वसूली व्यवस्था को लेकर होती ही है।

पास-फेल के मानदंड जरूरी

शिक्षा

स्वाति चंद्रा

केंद्र ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के दूसरे संशोधन (2019) के तहत कक्षा 5 तथा 8 की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले छात्रों को उसी कक्षा में न रोकने वाली नीति को खारिज कर दिया है, जो स्वागतयोग्य है। औपचारिक शिक्षा की उपलब्धता जितनी आवश्यक है, उतना ही जरूरी है उसका कारगर होना। छात्र निर्माण के वे शुरुआती वर्ष अहम होते हैं, जब छात्र ज्ञान अर्जन के साथ जीवन मूल्य भी सीख रहा होता है।

एक ओर जहां प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर बढ़ी है वहीं शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है। गुणवत्ता में गिरावट के यूं तो कई कारक हैं पर शिक्षा के मूल्यांकन में आई ढील इसमें बड़ा कारण है। हम विद्यार्थियों पर दबाव कम करने की कोशिश में उनके रास्ते से प्रतिस्पर्धा और परिश्रम का भाव ही खत्म करते जा रहे हैं। आजकल बच्चों में वैसे भी एकाग्रता की कमी होती है, और उनका ध्यान भटकाने के तमाम माध्यम उनके आसपास हैं। ऐसे में अगर उन पर आगे बढ़ने का प्रोत्साहन न हो और असफलता का डर भी न हो तो वो मेहनत करने से कतराते हैं। वैसे भी अब स्कूली मूल्यांकन पहले की तरह सख्त नहीं रहे। जहां एक ओर बच्चे शत-प्रतिशत अंक ला रहे हैं, वैसे में कुछ छात्र पास भी न हो पाएं तो यह शिक्षा की हार है। पर बच्चे फेल न हों, इसके लिए हम उन्हें मेहनत की ओर प्रोत्साहित न कर उन्हें फेल ही न करें, यह उन्हें अकादमिक रूप से और व्यक्तित्व निर्माण के पैमाने से भी कमजोर करना है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने जब प्राथमिक शिक्षा में आठवीं कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को मंजूरी दी थी तो उसका उद्देश्य था स्कूल ड्रॉपआउट रेट को कम करना। कई विद्यार्थी, जो गरीब घरों से आते हैं, अक्सर फेल हो जाने के बाद शिक्षा ही छोड़ देते हैं। नो डिटेंशन पालिसी के बाद स्कूल ड्रॉपआउट रेट में गिरावट जरूर आई पर इसलिए क्योंकि छात्रों का कोई समान मूल्यांकन ही नहीं हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार पांचवी कक्षा के 42% विद्यार्थियों की दक्षता दूसरी कक्षा के स्तर की भी नहीं थी। सरकारी विद्यालयों में आठवीं कक्षा के कई छात्र ठीक से लिख-पढ़ भी नहीं सकते। जब 2010 में दसवीं बोर्ड को खारिज कर सभी को पास करने देने की नीति आई थी, तब हमने देखा कि उसके परिणाम अच्छे नहीं रहे और इस नियम को 2018 में वापस ले लिया गया। परीक्षा का दबाव न होने से शिक्षक और शिक्षण प्रक्रिया, दोनों ढीले हो जाते हैं।

जहां कई स्कूल और अभिभावक इस बदलाव का स्वागत कर रहे हैं वहीं कई राज्य इसका विरोध भी कर रहे हैं। करीब 16 राज्यों ने इसे पहले ही स्वीकृति दे दी है जबकि तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया है! आलोचकों का कहना है कि इससे दलित और आदिवासी छात्र तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी ज्यादा प्रभावित होंगे और फेल होने की स्थिति में शिक्षा छोड़ने को मजबूर भी हो सकते हैं। अगर राजनीति से परे हो कर देखें तो क्या अकादमिक गुणवत्ता और समानता बिना किसी मानदंड के निश्चित की जा सकती है? क्या हम चाहते हैं कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, वो अकादमिक रूप से भी पिछड़े रहें? विद्यालय तो जाएं पर कुछ सीखने का या सफल होने का कोई उत्प्रेरक न हो! वास्तव में असफलता के भय से बड़ा प्रोत्साहन और उत्प्रेरक और कुछ नहीं होता। अगर कोई विद्यार्थी 40 प्रतिशत अंक भी नहीं ला पा रहा तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है लेकिन अगर उसे सीधे प्रोन्नति मिल जाती है तो उसे मेहनत करने और सीखने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। और जब तक उसे चीजें समझ में आने लगेंगी तब तक वह श्रम और कोशिश के महत्त्व से अनभिज्ञ रहेगा। जब उच्च शिक्षा उससे मेहनत की मांग करेगी तब वह उसके लिए मानसिक रूप से तैयार ही नहीं होगा! लेकिन प्राथमिक स्तर पर उसकी लापरवाही पर अवरोध लगाया जाए तो वह वक्त रहते संभलना सीख जाएगा।

हालांकि परीक्षा पास करना या अंक लाना ही शिक्षा के उद्देश्य नहीं हैं पर कहीं न कहीं एक मानदंड का होना जरूरी है। सतत मूल्यांकन जैसे प्रयास शत-प्रतिशत वहीं कारगर हो सकते हैं जहां सभी छात्र समान पृष्ठभूमि के हों और उन्हें घर पर भी सहायक वातावरण मिले। पर हमारे देश में कुछ छात्रों, जो शिक्षा मात्र डिग्री के लिए ग्रहण करते हैं, के लिए पास या फेल ही मानदंड होता है और यह मानदंड भी उनके रास्ते से हटा लिया जाए तो वे पंजीकृत छात्र तो रहेंगे पर शिक्षा के प्रति उनकी संजीदगी नहीं रहेगी। और उनकी आर्थिक स्थिति तो है ही उन्हें हर कदम पर शिक्षा से विमुख करने के लिए। आसान रास्ता हमेशा सही मार्ग नहीं होता।

हम आये दिन विद्यार्थियों पर बढ़ते प्रेशर की बात करते हैं। उन पर दबाव कम हो इसके लिए हमने सिलेबस कम कर दिए, मार्किंग स्कीम लचीली कर दी, प्राथमिक स्तर पर सीधे प्रोन्नति देने की नीति लागू की, लेकिन बच्चे अभी भी पढ़ाई का दबाव महसूस करते हैं। पर क्या हम उनके जीवन से प्रतिस्पर्धा को खत्म कर सकते हैं? क्या हमारे एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगिताएं अपना स्तर नीचे करेंगी? अगर नहीं, तो हमें बच्चों को सबल बनाना है, दक्ष बनाना है, और मानसिक रूप से जुझारू बनाना है। प्रतिस्पर्धा को मात्र प्रतिस्पर्धा की तरह लेना सिखाना है, जीत की तैयारी करते हुए हार का सामना करना भी सिखाना है, और इसकी शुरु आत औपचारिक शिक्षा से ही होती है। परीक्षा का डर खत्म करने के लिए परीक्षा ही खत्म कर देना समझदारी नहीं है। उसके लिए तैयार होना और नाकामी से उबर कर पुनः कोशिश करना यही छात्र जीवन के ध्येय होते हैं, परीक्षा तो माध्यम भर होती है।

यह संशोधन अगर्लाणी छात्रों को 2 महीने में फिर से परीक्षा देने का मौका देता है, और अगर तब भी कोई छात्र उत्तीर्ण नहीं हो पाता, तब उसे रोकने का प्रावधान है। अब विद्यालय प्रशासन को चाहिए कि ऐसे छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए, उनकी स्पेशल क्लासेज लगवाई जाएं ताकि वो अगली परीक्षा में पास हो सकें। बच्चे फेल न हों इसके लिए पूरी कोशिश होनी चाहिए पर उन्हें फेल ही न किया जाए, यह उनके आगे फेल न होने की गारंटी नहीं है।

(लेख में विचार निजी हैं)

चिकित्सा उपकरण क्षेत्र 2030 तक 30 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचने का आकलन

- चिकित्सा उपकरण क्षेत्र 2030 तक 30 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है
- सीआईआई की तरफ से आयोजित 21वें स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में भारत की चिकित्सा-प्रौद्योगिकी क्रांति की रूपरेखा शिखर सत्र में बताया गया, जापान, तीन और दे कोरिया के बाद भारत एशिया में चिकित्सा उपकरण का चौथा बड़ा बाजार है
- चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के तहत उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100-100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे

स्रोत : मीडिया इनपुट्स

बांग्लादेशी तमाशा : ऐसे निज़ाम, जिसके पास कोई संवैधानिक वैधता या जनादेश नहीं है-जो भीड़ की हिंसा के बल पर सत्ता पर काबिज हो गया है, ने भारत को रिक्वेस्ट भेजी है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री, जिन्हें उनके इस्तीफा देने से पहले ही सेना ने मजबूर करके भारत की तरफ धकेल दिया था, को उसे सौंपा जाए।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

बोरवेल | **कुमार समीर**

अटकतीं मासूम सांसें

खुले बोरवेल में अनजाने में कई बार ऐसी अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं, जो किसी परिवार, समाज को जिंदगी भर का असहनीय दर्द दे जाती हैं। ऐसा ही कुछ राजस्थान में हुआ है, जहां फिर से एक मासूम बच्ची बोरवेल में गिर गई। कोटपूतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी तीन साल की चेतना की सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। ऐसा ही 9 दिसम्बर को राजस्थान के ही दौसा जिले के कालीखाड़ गांव में पांच साल के आर्यन के साथ हुआ था। वह भी खुले बोरवेल में गिर गया था लेकिन 56 घंटे से अधिक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका।

ये दो घटनाएं दिसम्बर महीने में घटीं और राजस्थान की हैं, लेकिन हकीकत में देश के विभिन्न हिस्सों में खुले बोरवेल मासूम बच्चों के लिए काल बन रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ही सैकड़ों बच्चे बोरवेल में फंस कर दम तोड़ चुके हैं, लेकिन ऐसे हादसों पर लगाम कसने में सफलता नहीं मिल पा रही। न तो लोग ऐसे हादसों से चेतने को तैयार हैं, न प्रशासन की नींद टूट रही है। विडंबना है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए समाज में कोई जागरूकता नजर नहीं आती। ऐसे हादसों में बहुत कम बच्चों या लोगों को बचाने में सफलता मिलती है। एनडीआरएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में कई बच्चे बोरवेल में गिर चुके हैं, लेकिन उन्हें बचाने में 70 प्रतिशत रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम रहे। ऐसे हादसों को लेकर बड़ा प्रश्न है कि मासूम बच्चों की समाधि बनते बोरवेल हादसों को लेकर समाज से लेकर पूरा सिस्टम आखिर, कब गंभीर होगा? एनडीआरएफ के मुताबिक बोरवेल उपयोग के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर-1 पर है, और बोरवेल से जुड़े अधिसंख्य हादसों में छोटे बच्चे ही शिकार बनते हैं, जिनमें से 30 प्रतिशत के ही सुरक्षित बाहर निकाले जाने की संभावना होती है। बोरवेल में गिरने के करीब 92 प्रतिशत मामलों में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं। एनडीआरएफ की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार बोरवेल के पानी से शहरी और औद्योगिक जरूरतों की करीब 50 फीसद पूर्ति होती है। इससे कृषि संबंधी करीब 55 फीसद जरूरतें पूरी होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र तो पानी की अपनी जरूरतों के लिए 80 फीसद से भी ज्यादा बोरवेल पर निर्भर हैं। आंकड़े देखें तो भूगर्भ जल विभाग के अनुमान के

अनुसार देश भर में करीब 2.7 करोड़ बोरवेल हैं, लेकिन सक्रिय बोरवेल की संख्या, अनुपयोगी बोरवेल की संख्या और उनके मालिक का राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस नहीं है।

चिंता यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बावजूद सिस्टम ऐसे हादसों को लेकर गंभीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों, कानूनी संशोधनों और तमाम सख्ती के बावजूद ऐसे हादसे रुक नहीं रहे। बोरवेल खुदाई को लेकर अलग-अलग राज्यों के हाई कोर्ट के भी कई निर्देश हैं, और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी, जो सुनिश्चित करेंगे कि केंद्रीय या राज्य की एजेंसी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका का सही तरीके से पालन हो। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया, जस्टिस राधाकृष्णन और जस्टिस स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ ने बच्चों को गंभीर बोरवेल हादसों से बचाने के लिए एक रिट पिटीशन पर सुनवाई कर 6 अगस्त, 2010 को आदेश पारित किया था और उसी समय से यह फैसला देश भर में लागू है, लेकिन इसका सही तरीके से पालन कराया जाना आज तक सुनिश्चित नहीं किया गया है।

विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बावजूद ऐसे प्रयास होते नहीं दिखे, जिनसे ऐसे मामलों पर अंकुश लग सके। दिशा-निर्देशों के अनुसार बोरवेल की खुदाई से पहले कलेक्टर अथवा ग्राम पंचायत को लिखित सूचना देनी होगी। खुदाई करने वाली सरकारी, अर्धसरकारी संस्था या ठेकेदार का पंजीयन होना चाहिए। बोरवेल खुदवाने के कम से कम 15 दिन पहले डीएम, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को सूचना देना अनिवार्य है। खुदाई वाले स्थान पर साइन बोर्ड लगाया जाना चाहिए। खुदाई के दौरान आसपास कंटीले तारों की फेंसिंग की जानी चाहिए। फेंसिंग पाइप के चारों ओर सीमेंट या कंक्रीट का 0.3 मीटर ऊंचा प्लेटफार्म बनाना चाहिए। बोरवेल के मुहाने पर स्टील की प्लेट वेल्ड की जाएगी या उसे नट-बोल्ट से अच्छी तरह कसना होगा। बोरवेल की खुदाई पूरी होने के बाद खोदे गए गड्ढे और पानी वाले मार्ग को समतल किया जाएगा। खुदाई अधूरी छोड़ने पर मिट्टी, रेत, बजरी, बोल्डर से बोरवेल को जमीन की सतह तक भरा जाना चाहिए। इन दिशा-निर्देशों का पालन होता कहीं नहीं दिख रहा। न ही नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होती दिखती है। हालांकि बोरवेल हादसा होने के बाद प्रशासन द्वारा बोरवेल खुला छोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चला कर सख्ती की बातें हर बार दोहराई जाती हैं, लेकिन सख्ती की बातें अप्रिय घटना सामने आने पर लोगों में उपजे आक्रोश के शांत होने तक ही बरकरार रहती हैं।

उपासना | श्रीराम शर्मा आचार्य

आप लोगों को मालूम है कि ग्वाल-बाल इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने अपनी लाठी के सहारे गोवर्धन को उठा लिया था। इसी तरह रीछ-वंदर इतने शक्तिशाली थे कि बड़े-बड़े पत्थर उठा कर लाए और समुद्र में सेतु बना कर उसे लांघ गए थे। क्या यह उनकी शक्ति थी? नहीं बेटे, यह भगवान श्रीकृष्ण एवं राम के प्रति उनके समर्पण की शक्ति थी, जिसके बल पर वे इतने शक्तिशाली हो गए थे। आप कृपा करके मछली, चिड़िया पकड़ने वालों के तरीके से मत बनना और न इस तरह की उपासना करना जो आटे की गोली और चावल के दाने फेंक कर उन्हें फंसा लेते और पकड़ लेते हैं। ऐसे उपासक मत बनना जो भगवान को फंसाने के लिए तरह-तरह के प्रलोभन फेंकता है। बिजली का तार लगा हो परंतु उसका संबंध जनरेटर से न हो तो करंट कहां से आएगा? उसी तरह हमारे अंदर अहंकार, लोभ, मोह भरा हो तो वे चीजें हम नहीं पा सकते जो भगवान के पास हैं। अपने पिता की संपत्ति के अधिकारी आप तभी हो सकते हैं, जब आप उनका ध्यान रखते हों, उनके आदर्शों पर चलते हों। आप अपना सारा बेतन अपनी पाकेट में रखते थे और उनकी हारी-बीमारी से हमारा कोई लेना-देना नहीं था, तो फिर आपको उनकी संपत्ति का कोई अधिकार नहीं मिलने वाला। साथियो, हमने भगवान को देखा तो नहीं है, परंतु अपने गुरु को हमने भगवान के रूप में पा लिया है। उनको हमने समर्पण कर दिया है। उनके हर आदेश का पालन किया है। इसलिए आज उनकी सारी संपत्ति के हम हकदार हैं। आपको मालूम नहीं है कि विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को देखा था, स्वामी दयानंद ने विरजानंद को देखा था। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त का नाम सुना है न आपने। उनके गुरु ने जो उनको आदेश दिए, उनका उन्होंने पालन किया। गुरुओं ने शिष्यों को, भगवान ने भक्तों को जो आदेश दिए, वे उनका पालन करते रहे। आपने सुना नहीं है, एक जमाने में समर्थ गुरु रामदास के आदेश पर शिवाजी लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। उनके एक आदेश पर वे आजादी की लड़ाई के लिए तैयार हो गए। यही समर्पण का मतलब है। आपको मालूम नहीं है कि इसी समर्पण की वजह से समर्थ गुरु रामदास की शक्ति शिवाजी में चली गई और वे उसे लेकर चले गए।

रीडर्स मेल

ईडी पर नकेल प्रतिगामी होगी

जुलाई, 2022 में केंद्र सरकार ने संसद के एक सत्र में स्वीकार किया था कि प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 5,422 मामले दर्ज किए थे, लेकिन केवल 23 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया जो 0.5 फीसद से भी कम है। इसका मतलब हुआ कि सारे मामले राजनीतिक दबाव के कारण दर्ज किए गए थे? दो दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने इसी वजह से ईडी पर नकेल कसते हुए कहा है कि वो नागरिकों के जब्त मोबाइल, लैपटॉप जैसे उपकरणों तक न तो पहुंच सकती है और न ही उनकी कॉपी कर सकती है। वैसे, अदालत का यह फैसला आया तो लॉटरी किंग के रूप में जाने जाने वाले सैंटियागो मार्टिन मामले में है, लेकिन माना जा रहा है कि इस फैसले का असर अब ईडी से जुड़े दूसरे केसों पर भी पड़ सकता है। केंद्र सरकार के हाथ में ईडी के रूप में, विपक्षियों, कार्यकर्ताओं एवं आलोचकों को डराने का हथियार है, उसकी धार तो और भी कम हो जाएगी।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

भागवत के बयानों पर आपत्ति

संघ प्रमुख मोहन भागवत के धार्मिक बयानों से शायद आजकल संत समाज नाराज दिख रहा है। पिछले दिनों भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना ठीक नहीं। उनकी इन्हीं बातों को लेकर संत समाज नाराज है। उसका कहना है कि यह बयान अल्पसंख्यकों को खुश करने वाला अधिक दिखता है। अतः इसी पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने अपने बयान में कहा है कि मोहन भागवत संघ प्रमुख हैं परंतु हिन्दू धर्म के प्रमुख नहीं हैं तथा उनकी बातों पर अमल करना जरूरी नहीं है। फिर हिन्दू समाज के लिए उनके अपने धार्मिक संत एवं शंकराचार्य मौजूद हैं। अतः भागवत को अपने किसी भी बयान में हिन्दू समाज को संबोधित नहीं करना चाहिए क्योंकि वह कोई हिन्दू समाज के धर्मगुरु नहीं कहलाए जाते। रामभद्राचार्य जगतगुरु का कहना है कि हिन्दुओं के धार्मिक स्थल उनके अपने हैं एवं उनका ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्व भी है। अतः अगर कोई उन्हें पाने का प्रयास करता है तो उसका समर्थन करना चाहिए। इसी तरह से एक अन्य शंकराचार्य ने भी इस बात का समर्थन करते हुए मोहन भागवत को धार्मिक बयान नहीं देने की बात कही है।

एमएम राजावत 'राज', शाजापुर, मप्र

एक मानसिकता होता है नया साल

नया साल केवल एक दिन नहीं है; यह एक मानसिकता है। यह हमें उम्मीद से भर देता है, जो हमारे सपनों और आकांक्षाओं को प्रेरित करती है। यह उम्मीद एक सामूहिक चाहत से जन्म लेती है कि दुनिया बेहतर हो, प्रेम, एकता और अवसरों से भरी हो। हर व्यक्ति इस उम्मीद को संजो कर न केवल अपनी, बल्कि अपने आसपास की जिंदगियों को भी प्रभावित करता है। उम्मीद इस विश्वास पर आधारित है कि बदलाव संभव है। असफलताओं और चुनौतियों के बावजूद नये साल का आगमन याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। अतीत के सबक हमें भविष्य को संभालने की ताकत और ज्ञान देते हैं। अपने सपनों की ताकत में विश्वास करें, एक-दूसरे का समर्थन करें और दयालुता, करुणा और संभावनाओं से भरी दुनिया बनाने के लिए काम करें। नया साल, नई उम्मीद एक उज्जवल कल का वादा आज से शुरू होता है।

चंदन कुमार नाथ, बरपेटा, असम
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काज़मी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, स्काईवॉक, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - मनेश सिंह*।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

चिंतन

चीन में ब्रह्मपुत्र पर बांध से भारत की बढ़ेगी दिक्कत

सीमा से इतर चीन एक और विवाद को जन्म दे रहा है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना कर जल को नियंत्रित करने का मंसूबा बना रहा है। चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक तिब्बत में यारलुंग जांग्बो नदी (ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम) पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दी है, जिससे भारत और बांग्लादेश की चिंता बढ़ना लाजिमी है। यह बांध परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी, जिस पर 137 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत आएगी। यह बांध हिमालय की एक विशाल घाटी में बनाया जाएगा, जहां ब्रह्मपुत्र नदी एक विशाल 'यू-टर्न' लेकर अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश में बहती है। विश्व की छठी बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र भौगोलिक रूप से कठिन परिस्थितिकी तंत्र वाली नदी है, जिसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ इस क्षेत्र के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। चीन भीषण जल संकट से भी गुजर रहा है, तिब्बत क्षेत्र में जलापूर्ति के लक्ष्य के साथ चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर पनबिजली प्रोजेक्ट बना रहा है। भारत व बांग्लादेश को इसका विरोध करना चाहिए और जलसंधि का पालन होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के बड़े बांध को लेकर भारत की असल चिंता इसके जलप्रवाह को रोकने और शत्रुता के समय सीमावर्ती क्षेत्र में भारी मात्रा में पानी छोड़ने की स्थिति को लेकर है। यूं तो भारत भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र पर बांध बना रहा है, पर यह जल नियंत्रण के लिए नहीं है, बल्कि नदी के खतरे को कम करने के लिए है। भारत व चीन के बीच एलएसी की तरह ब्रह्मपुत्र नदी विवाद भी नासूर की तरह है। भारत और चीन ने सीमा पार नदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2006 में एक विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (ईएलएम) की स्थापना की थी, जिसके तहत चीन बाढ़ के मौसम के दौरान भारत को ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी पर जल विज्ञान संबंधी जानकारी प्रदान करता है। भारत, चीन के सीमा मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधियों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच 18 दिसंबर को यहां हुई वार्ता में सीमा पार की नदियों के बारे में डेटा साझा करने का मुद्दा उठा था। ब्रह्मपुत्र बांध में इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि परियोजना स्थल टेक्टोनिक प्लेट क्षेत्र से लगा हुआ है, जहां भूकंप आते हैं। पर चीन ने भूकंप के बारे में चिंताओं को दरकिनार कर ब्रह्मपुत्र बांध जलविद्युत परियोजना को स्वीकृति दी है, जो संकटकारी मूव है। कैलाश पर्वत के पास एंगसी ग्लेशियर से निकलती और पूर्व में हिमालय से घिरी ब्रह्मपुत्र नदी 3,969 किलोमीटर लंबी है। इस नदी पर चीन की पनबिजली प्रोजेक्ट इस नदी को एक मौसमी नदी में बदल देगी, जिसका परिणाम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सूखे के रूप में सामने आ सकता है। एक खतरा यह भी है कि बांधों के निर्माण के पश्चात जब चीन मानसून में बाढ़ का पानी छोड़ेगा तो इससे ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह में वृद्धि होगी, इससे भारतीय क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होगा। नदियों के आस-पास जल संबंधी परियोजनाओं के चलते चीन ने अपनी नदियों को काफी प्रदूषित किया है और इसके कारण चीन से भारत की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के जल की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। चीन के इस कदम से ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर निर्भर असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में भी पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। कोई भी विकास मानव के विनाश का मार्ग नहीं बना सकता है। चीन को बृहत मानवीय हित में फैसला लेना चाहिए।

उम्मीद
अरविंद जयतिलक

केन-बेतवा परियोजना से संवरेगा बुंदेलखंड

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के शुभारंभ से बुंदेलखंड में विकास और प्रगति का एक नया सूर्योदय होना तय है। दशकों से पेयजल और सिंचाई संकट का सामना कर रहे बुंदेलखंडवासियों के लिए यह परियोजना किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसा इसलिए कि इस परियोजना से कृषि उत्पादन बढ़ेगा और लोगों की आय में वृद्धि होगी। कृषि पर आधारित उद्योग-धंधे विकसित होंगे और अर्थव्यवस्था का पहिया नाच उठेगा। आय बढ़ने से समृद्धि का नया द्वार खुलेगा। गौर करें तो इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के साथ-साथ मध्यप्रदेश राज्य के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी तथा उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी व ललितपुर जिले जलसंकट से मुक्त होंगे। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना को आकार देने के लिए वर्ष 2021 में मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश की सरकार ने विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया था।

इस समझौते के तहत इस परियोजना पर तकरीबन 44,605 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। इसका 90 फीसद खर्च भार केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाना सुनिश्चित हुआ जबकि उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश दोनों सरकारें दस फीसदी यानी पांच-पांच फीसदी खर्च करेंगे। तब केंद्र सरकार ने इस योजना को पूरा करने के लिए आठ साल का समय सुनिश्चित किया। यह तो है इस परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्यप्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना है। उल्लेखनीय है कि केन नदी मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है जिसकी कुल लंबाई 470 किमी है। यह नदी मध्यप्रदेश के कटनी जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है। केन नदी 292 किमी मध्यप्रदेश में बहती है। लेकिन उसके जल का उपयोग मध्यप्रदेश नहीं कर पाता है। अब केन-बेतवा परियोजना के तहत दौधन के पास एक बैराज बनाकर केन नदी के जल को रोका जाएगा। दौधन बांध से तकरीबन 221 किमी लंबी एक लिंक नहर का निर्माण कर केन बेसिन के 1074 मिलियन क्यूसेक मीटर अधिशेष जल को बेतवा बेसिन में पहुंचाया जाएगा। बेतवा नदी की भौगोलिक स्थिति पर दृष्टि डालें तो यह मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में बहती है। इसे यमुना नदी की उपनदी भी कहा जाता है। यह मध्यप्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर जिलों से गुजरती हुई तकरीबन 480 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यमुना नदी में मिलती है। अगर यह परियोजना जमीन पर उतरती है तो इस संकट की मार झेल रहे बुंदेलखंड के लोगों की प्यास बुझेगी तथा कृषि योग्य भूमि लहलहाएगी। देखें तो इस परियोजना से उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश की तकरीबन 1062 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। उत्तर प्रदेश के इन चार जिलों में रहने वाले तकरीबन 65 लाख लोगों की प्यास भी बुझेगी। झांसी को 14.66 एमसीएम, ललितपुर को 31.98 एमसीएम तथा महोबा को 20.13 एमसीएम पेयजल मिलेगा। इस

परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश में दो बैराज भी बनने हैं जिससे 103 मेगावाट जल ऊर्जा और 27 मेगावाट सौर उर्जा का उत्पादन किया जा सकेगा। गौरतलब है कि केन-बेतवा परियोजना की पहली रूपरेखा 2002 में तैयार की गयी थी। वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश के बीच पानी बंटवारे का समझौता हुआ लेकिन यह परियोजना बर्फखाने में चली गई। 2006 में पहली बार परियोजना के सर्वे के लिए जल विकास अधिकरण का गठन हुआ लेकिन फिर भी परियोजना परवान नहीं चढ़ी। 2019 में दोनों राज्यों में पुनः जलसमझौते को आकार देने की कोशिश हुई लेकिन बात नहीं बनी। उसका कारण यह था कि मध्यप्रदेश पूरे साल का पानी एक साथ उत्तर प्रदेश को देने की बात कर रहा था जबकि उत्तर प्रदेश फसली सीजन के मुताबिक पानी मांग रहा था। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना के लिए हरी झंडी दिखा दी है जिससे बुंदेलखंड की तस्वीर बदलनी तय है।

ध्यान दें तो बुंदेलखंड में पानी की कमी का मुख्य कारण नदी-नीति की विफलता ही रहा है। इस कारण आज तक चंबल, सिंध पहुज, बेतवा, केन, धसान, पयस्वनी इत्यादि उद्गम स्रोत होते हुए भी समूचा विंध्य क्षेत्र जलविहिन है। अगर इन नदियों के जल का संचय और सदुपयोग किया गया होता तो बुंदेलखंड में जल की कमी नहीं होती। लेकिन सच्चाई यह है कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या दूर करने के लिए जितनी भी योजनाएं गढ़ी-बुनी गई, वह परवान नहीं चढ़ सकी। एक आंकड़े के मुताबिक बुंदेलखंड में औसतन 70 हजार लाख टन घन मीटर पानी प्रतिवर्ष वर्षा द्वारा उपलब्ध होता है। लेकिन विडंबना है कि इसका अधिकांश भाग तेज प्रवाह के साथ निकल जाता है। बेतवा नदी का प्रभाव ठुकवां बांध पर वर्षा ऋतु में 16800 घन मीटर प्रति सेकेंड होता है जो ग्रीष्म में घटकर 0.56 घन मीटर प्रति सेकेंड रह जाता है। इसी तरह पयस्वनी का प्रभाव वर्षा ऋतु में 2184 घन मीटर प्रति सेकेंड रहता है जबकि ग्रीष्म ऋतु में यह 0.42 घन मीटर प्रति सेकेंड रह जाता है। अगर इन प्रवाहों को संचित कर उपयोग में लाया जाए तो इस क्षेत्र की भूमि को लहलहाते देर नहीं लगेगी। गौर करें तो केन और बेतवा को छोड़कर अन्य नदियों का जल बिना उपयोग के यमुना नदी में प्रवाहित हो जाता है। बुंदेलखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 70 हजार वर्ग किलोमीटर है। यह वर्तमान हरियाणा और पंजाब से अधिक है। इसमें उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के 13 जनपद तथा समीपवर्ती भू-भाग है जो यमुना और नर्मदा नदी से आबद्ध है। मध्यप्रदेश के सागर संभाग के पांच जिले-छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर और दमोह और चंबल का दतिया जिला मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड में आते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के झांसी संभाग के सभी सात जिले- बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा और हमीरपुर बुंदेलखंड में आते हैं। यह बुंदेलखंड की विडंबना है कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक एकरूप भौगोलिक क्षेत्र होने के बावजूद यह दो राज्यों में बंटा हुआ है। बावजूद इसके बुंदेलखंड विकास की असिमित संभावनाओं को अपनी कोख में संजोए हुए है। उसके पास इतने अधिक संसाधन है कि वह अपने बहुमुखी उत्थान की आर्थिक व्यवस्था स्वतः कर सकता है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब उसकी कोख जल से संतृप्त होगी। उल्लेखनीय है कि बुंदेलखंड की दुर्दशा को ध्यान में रखकर ही 1956 में गठित प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाए जाने की वकालत की गई थी। बहरहाल बुंदेलखंड के अलग राज्य का सपना तो दूर है, लेकिन केन-बेतवा परियोजना से उम्मीद की आस बंध गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इस परियोजना में किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

जयंती विशेष
विवेक शुक्ला

ग़ालिब से 'गुफ्तगू' करते मंटो

वह 1940 का दशक था। देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। देश और दिल्ली में भी लगातार आंदोलन हो रहे थे। मशहूर उर्दू लेखक सआदत हसन मंटो उन दिनों दिल्ली में थे। वे ऑल इंडिया रेडियो में काम कर रहे थे। मंटो के साथ उर्दू के मशहूर अफसाना निगार कृष्ण चंदर भी काम करते थे। जब भी उन्हें खाली समय मिलता, वे दोनों दिल्ली की खाक छानने के लिए निकल पड़ते। यह नामुमकिन है कि वे दोनों दिल्ली-6 में मिर्जा ग़ालिब के घर और बस्ती निजामुद्दीन में उनकी कब्र पर कभी न गए हों। मंटो ने दिल्ली में रहते हुए 'मिर्जा गालिब' फिल्म लिखी थी। वे 1955 में रीलिज हुई थी। आप बस्ती निजामुद्दीन में मिर्जा ग़ालिब की मजार की ओर बढ़ते हुए मंटो और उन सभी के बारे में पलभर को सोचते हैं जो मिर्जा ग़ालिब की कब्र पर आते रहे हैं। आप गालिब की मजार पर जाते हुए ग़ालिब अकादमी के आगे से गुजरते हैं। वहां पर आज उनकी साल गिरह पर उनकी शायरी पर कई विद्वान गुफ्तगू करेंगे। मुशायरा भी होना है। यहां से गुजरते हुए आपके कानों में 'ये न थी हमारी किस्मत के विसाल-ए-यार होता...' या 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले...' जैसे गालिब के कालजयी शेर सुनाई पड़ते हैं। कोई शायर या गालिब की शायरी को चाहने वाला इन्हें पढ़ रहा होता। खैर साहब, आप ग़ालिब की मजार पर पहुंचते हैं। वहां पर पहले से गालिब की शायरी के कुछ शैदाई पहुंचे हुए हैं। कुछ नौजवान वहां आए हुए हैं। उनमें से एक कहता है, 'हम हर साल यहां आते हैं। यहां आकर लगता है कि हम गालिब साहब से बात कर रहे हैं। हम उनकी शायरी को पढ़ते हैं। उर्दू शायरी पढ़ने वाले और गालिब पर गंभीर रिसर्च करने वाले भी यहां आते हैं। एक दौर था, जब यहां पाकिस्तानी भी नियमित रूप से दस्तक देते थे। वह उन दिनों की बात है जब दोनों देशों के नागरिक सरहद के आर-पार आराम से आते-जाते थे। ग़ालिब अकादमी के सचिव डॉ. अकील अहमद कहते हैं, 'जो ग़ालिब के गहरे दार्शनिक विचारों पर शोध करते हैं, वे भी यहां हैं। ग़ालिब की मजार आज जिस रूप में है, इसे खड़ा करने में हमदर्द दवाखाना के फाउंडर हकीम अब्दुल हमीद का अहम रोल था। उन्होंने ही गालिब अकादमी स्थापित की थी। वे कहते थे कि मजार और इसके आसपास हालत काफी खराब थी। उन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया। अगर बात ग़ालिब अकादमी की करें तो, इसका उद्घाटन 1969 में राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन ने किया था। यहां ग़ालिब को समर्पित एक संग्रहालय है, जिसमें उनकी प्रतिमा, दुर्लभ पुस्तकें, दस्तावेज और प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की एक गैलरी है। हकीम अब्दुल हमीद ने इस लेखक को 1995 में बताया था, " गालिब की मजार का क्षेत्र जर्जर था जब तक कि उन्होंने इसे पुनर्जीवित करने के लिए कदम नहीं उठाया था।" मशहूर टीवी पर्सनैलटी विनोद दुआ भी गालिब की मजार पर हाजिरी देने के लिए आते थे। वे गालिब को दिल्ली वालों का बुजुर्ग कहते थे। मुहम्मद इकबाल भी ग़ालिब की शायरी से गहरे से प्रभावित थे। वे कहते थे कि उनकी कब्र पर आना शायरों के लिए किसी तीर्थयात्रा के समान है। वे ग़ालिब और हजरत निजामुद्दीन औलिया की मजारों पर हाजिरी देते थे। वे यहां पहली बार 1905 में आए थे, इंग्लैंड जाने से ठीक पहले। इस बीच, दिल्ली में लगभग दो साल रहने के बाद, मंटो अपने पसंदीदा शहर, मुंबई (तब बॉम्बे) लौट गए थे। वह 1948 की बात है। 'मिर्जा ग़ालिब' की कहानी लिखते समय, वे निश्चित रूप से ग़ालिब के घर और कब्र पर जाते ही होंगे। उनका एक तरह से अपने प्रिय शायर से 'संवाद' भी हुआ होगा। वे जरूर सोचते होंगे कि अगर गालिब साहब उनके सामने होते तो वे उनसे क्या सवाल करते। सोहराब मोदी ने मंटो की कहानी पर मिर्जा गालिब फिल्म का निर्माण किया। उसे जबरदस्त सफलता मिली थी। देश के विभाजन के बाद, मंटो पाकिस्तान चले गए। उनका 1955 में लाहौर में निधन हो गया। इत्तेफाक देखिए कि तब देशभर में 'मिर्जा ग़ालिब' फिल्म चल रही थी। राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे देखा और पसंद किया। मंटो की मौत से अवाक किशन चंदर ने तब लिखा था- 'जिस दिन मंटो से मेरी पहली मुलाक़ात हुई, उस रोज मैं दिल्ली में था। आज दिल्ली में मिर्जा ग़ालिब पिक्चर चल रही है। इसकी कहानी इसी दिल्ली में, मोरी गेट में बैठ कर मंटो ने लिखी थी।' 'मिर्जा ग़ालिब' 1954 में रिलीज हुई तो उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में भी हुई। मिर्जा गालिब ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक और हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक जीता। मिर्जा गालिब फिल्म ने उस अजीम शायर को जिंदा कर दिया था। इसका श्रेय मंटो को भी जाता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

घृणा का अर्थ आत्मा द्वारा आत्मा का विनाश

संकलित
दर्शन

सब प्रकार की घृणा का अर्थ है आत्मा के द्वारा आत्मा का विनाश। प्रेम ही जीवन का यथार्थ नियामक है। प्रेम कभी निष्फल नहीं जाता। चाहे आज हो, चाहे सैकड़ों युगों के पश्चात प्रेम की विजय होगी और जरूर होगी। क्या तुम मनुष्य जाति से प्रेम करते हो? भगवान की खोज में कहीं जाते हो? दरिद्र दुखिया और दुर्बल क्या ये सभी तुम्हारे ईश्वर नहीं हैं। पहले उनकी उपासना क्यों नहीं करते? गंगा किनारे रहकर कुआं किसलिए खोदते हो। प्रेम की सर्वशक्तिमान पर विश्वास करना सीखो। क्या तुम्हारे हृदय में प्रेम है। यदि है तो तुम सर्वशक्तिमान हो। क्या तुम्हें एक भी कामना नहीं कामनाओं से बिलकुल विहीन हो। यदि ऐसा है तो तुम्हारी शक्ति को रोकने की सामर्थ्य किसमें है। अपने चरित्र के बल से मनुष्य सब जगह विजयी हो सकता है। भगवान आपकी संतान की रक्षा समुद्र के भीतर भी किया करते हैं। तुम्हारी मातृभूमि वीर संतान मांगती है। तुम लोग वीर बनो। जिनकी समदृष्टि हो गई है, वे ब्रह्म में अवस्थित माने जाते हैं। प्रेमावस्था को प्राप्त करना सिद्धावस्था है, किंतु हम जितना ही सिद्धि की ओर अग्रसर होते हैं, उतना ही कम काम करते हैं। सात्विक व्यक्ति समझते और देखते हैं कि सब कुछ खिलवाड़ मात्र है, इसी से वे किसी चीज में सिर नहीं खपाते। निर्विघ्न उद्देश्य सिद्धि के लिए चटपट कोई काम कर डालना उचित नहीं, सिद्धि प्राप्ति के लिए इन तीनों गुणों पवित्रता, सहनशीलता और अध्यवसाय और सबसे अधिक प्रेम की आवश्यकता है।

ज्ञान मार्ग नहीं, तो दूसरा विकल्प है भक्ति

संकलित
प्रेरणा

धर्म आत्म विस्मरण नहीं है, धर्म है परिपूर्ण रूप से आत्म स्मरण। स्वयं को भूल नहीं जाना है, स्वयं को उसकी परिपूर्णता में जान लेना है। स्वयं को किसी में डुबा नहीं देना है, बल्कि खुद को अपनी समग्रता में पहचान लेना है। ज्ञान ही रोक लेता है, अटका लेता है। ज्ञान का बोझ मन को इतना भारी कर देता है कि फिर सत्य तक की यात्रा करना कठिन हो जाती है। ज्ञान के तट से जिनकी नाव बंधी है, वे सत्य के सागर में यात्रा नहीं कर सकेंगे। स्वभावतः यदि ज्ञान मार्ग नहीं है, तो एक दूसरा विकल्प है भक्ति और कल्पना का। यदि ज्ञान सत्य का द्वार नहीं है, तो फिर भक्ति है, समर्पण है, भावना है, कल्पना है। भक्ति भी मार्ग नहीं है। यदि ज्ञान मार्ग नहीं है, तो कल्पना तो और भी मार्ग नहीं हो सकती है। ज्ञान यदि द्वार नहीं है, तो स्वप्न तो और भी द्वार नहीं हो सकता है। ज्ञान है तर्क भक्ति है स्वप्न। ज्ञान है विचार, भक्ति है कल्पना। मनुष्य का मन या तो तर्क करना जानता है या कल्पना। मनुष्य के मन की क्षमता है उन स्वप्नों को देख लेने की, जो वास्तविक नहीं हैं। बल्कि मन जिन बातों को देखना चाहता है, स्वप्न या कल्पना में उन्हें देख लेता है। जिसे जीवन में नहीं उपलब्ध कर पाता, उसे सपने में पा लेता है। हम सभी सपने देखते हैं। स्वप्न परिपूरक हैं। जिंदगी में यथार्थ में जो नहीं मिलता, स्वप्न उसे पूरा कर देते हैं। तो जिस सत्य को ज्ञान से, विचार से नहीं खोजा जा सका, सोचा होगा कि उसे हम स्वप्न, कल्पना से और भावना से पा लेंगे। लेकिन मनुष्य का मन जो भी कल्पना करेगा, वह उसके मन की सृष्टि होगी जो सत्य नहीं है।

अंतर्मन

आज की पाती

हिंदुओं पर अत्याचार रुकना चाहिए

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। मां-बेटियों का उत्पीड़न जोरों पर है। हिंदुओं के मंदिरों और पूजा स्थलों को नष्ट किया जा रहा है। इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आगे आना चाहिए। कट्टरपंथी इस कदर हावी हैं कि किसी की सुनते नहीं। कानून नाम की वहां कोई चीज नहीं है। मानवतावादी संगठन इन अत्याचारों पर मौन क्यों हैं? उन्हें वैध तरीके से भी भारत नहीं आने दिया जाता। संतों को जेलों में डाला जा रहा है। वहां न वकील, न दलील चल रही है। पैरवी करने वालों को घायल किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बैनर्जी ने ठीक ही संयुक्त राष्ट्र से शांति सेना भेजने की मांग की है। समय आ गया है कि 1971 के इतिहास की आवृत्ति हो। अब कट्टरपंथी सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। भारत के सभी दलों को भारतवंशियों की चिंता करनी चाहिए। *-वंश कुमार रायपुर*

ट्रेंड

नायर के निधन से दुखी

मलयालम सिनेमा और साहित्य के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक एमटी वासुदेवन नायर जी के निधन से दुखी हूं। मानवीय भावनाओं की गहन खोज के साथ उनके कार्यों ने पीढ़ियों को आकार दिया है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

दल से बड़ा देश

जब मैं वाजपेयी जी था, तब मैं अटल जी से मिला और उनसे अनुरोध किया कि वे असम में पंचायत चुनाव कराने में सहायता करें, क्योंकि राज्य सरकार के पास धन की कमी थी। अटल जी तुरंत सहमत हो गए। उनके लिए देशहित दल से बड़ा देश था।
-हिमंत बिस्वा सरमा, असम सीएम

कांग्रेस का दोहरा चरित्र

इससे कांग्रेस के दोहरे चरित्र का भी पर्दाफाश होता है कि वह पूर्वोत्तरों का विरोध करके संसद अवरोध करती है किन्तु उन्हीं धन्नासेठों से धन लेकर चुनाव लड़ती है और सरकार बनने पर उन्हें लाभ पहुंचाने का कार्य करती है।
-मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

फार्मा उद्योग 14वें स्थान पर

उत्पादन के मूल्य के हिसाब से भारतीय फार्मा उद्योग विश्व स्तर पर 14वें स्थान पर है। जेनेरिक दवाओं, ओटीसी, टीकों आदि हमारे विविध उत्पाद पोर्टफोलियो ने हमें यह अद्वितीय स्थान हासिल करने में मदद की है।
-किरण मजूमदार-शॉ, उद्योगी

करंट अफेयर

भारत से पंगा लेने वाले ट्रूडो को ट्रंप ने कहा पागल वामपंथी

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से पंगा लेने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उनकी औकात दिखानी शुरू कर दी है। ट्रंप ने क्रिसमस के मौके पर ट्रूडो को वामपंथी पागल तक कह डाला। ट्रंप ने एक पर लिखा, लगातार हमारी न्यायिक प्रणाली का कार्यों और चुनावों में बाधा डालने की कोशिश कर रहे कट्टर वामपंथी पागलों को क्रिसमस की शुभकामनाएं। साथ ही कनाडा पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी भी दी। ट्रंप ने ट्रूडो को एक बार फिर सुझाव दिया कि बेहतर है कि वह कनाडा का अमेरिका में विलय कर दें। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक संदेश में फिर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि अगर ट्रूडो ऐसा करते हैं तो उन्हें इसका फायदा ही फायदा होगा और अमेरिका 60 फीसदी तक कर छूट देगा। इससे कनाडा की अर्थव्यवस्था को दूनी रफ्तार मिलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बनाने का भी ऑफर दिया। ट्रंप का ये ऑफर ट्रूडो के गले की ऐसी फांस बन गया है, जिसे वह न तो स्वीकार कर पा रहे हैं और न ही इन्कार कर पा रहे हैं। ट्रंप की नजर कनाडा के साथ ही साथ पनामा नहर पर भी गड़ी हुई है।

ऑफ बीट

नागवासुकी मंदिर में नागों के राजा ने किया था विश्राम

धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में एक है नागवासुकी मंदिर। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन बिए बिना संगम से लौटना अधूरी यात्रा के बराबर है। इसलिए यदि आप महाकुंभ जाएं, तो नागवासुकी मंदिर के दर्शन कर खुद को कृतार्थ करें। जब औरंगजेब का भाला भी नहीं आया काम- धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज के संगम तट से उत्तर दिशा की ओर दारागंज के उत्तरी कोने पर अति प्राचीन नागवासुकी मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागों के राजा वासुकी नाग विराजमान रहते हैं। कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब भारत में मंदिरों को तोड़ रहा था, तो वह नागवासुकी मंदिर को खुद तोड़ने पहुंचा था। जैसे ही उसने मूर्ति पर भाला चलाया, तो अचानक दूध की धार निकली और चेहरे के ऊपर पड़ने से वो बेहोश हो गया था। अंत में उसे हताश और निराश होकर वापस लौटना पड़ा। तब से लेकर आज तक इस प्राचीन मंदिर की महिमा का गुणगान चारों दिशाओं में हो रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने नागवासुकी को सुमेरु पर्वत में लपेटकर उनका प्रयोग रस्सी के तौर पर किया था, वहीं समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी पूरी तरह लहूलुहान हो गए थे और भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने प्रयागराज में इसी जगह आराम किया था।

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शुक्रवार, 27 दिसंबर 2024

सही निकला डर

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है, उससे दोनों देशों के रिश्ते में बेहतरी आने के बजाय खटास और बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। खासकर, जिस तरह से बांग्लादेश की पाकिस्तान से करीबी बढ़ रही है, वह भारत के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है।

सत्ता परिवर्तन का असर | पड़ोसी मुल्क में हलिया सत्ता परिवर्तन सहज लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं था। इसलिए उसके बाद थोड़ी अफरातफरी स्वाभाविक थी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ ही जिस तरह से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ, वह अंतरिम सरकार गठित होने के बाद भी जारी रहा। यह इस बात का संकेत था कि बांग्लादेश का नया नेतृत्व या तो इस्लामी कट्टरपंथी तत्वों के बहुत ज्यादा प्रभाव में है या उन पर अंकुश लगाने में असमर्थ है।

बांग्लादेश-पाक में बढ़ती करीबी

तनाव बढ़ाने वाला रुख | लंबी सरहद वाले इस पड़ोसी मुल्क में इस तरह का घटनाक्रम भारत को प्रभावित करता है। लिहाजा, भारत ने ठीक ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से बार-बार कहा कि वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। मगर वहां की सरकार हिंसा की इन घटनाओं को झुठलाने में लगी रही। इसके साथ ही उसने ऐसा रुख अपनाना शुरू किया जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है।

हसीना के प्रत्यर्पण पर जोर | ताजा उदाहरण है बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग। दोनों देशों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि में राजनीतिक प्रत्यर्पण की बात नहीं है, फिर भी इस संधि के हवाले से उस पर जोर दिया जा रहा है। भारत ने इस पर खामोशी बनाए रखी है, लेकिन यह सवाल तो है ही कि क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जाने-अनजाने इस मांग के जरिए उसे असुविधाजनक स्थिति में डालने की इच्छा रखने वालों का अजेंडा आगे बढ़ा रही है।

पाक से करीबी | यह सब जैसे काफी न था, बांग्लादेश की सरकार ने पाकिस्तान के साथ आइवर्थजनक तेजी से संबंध सुधारने शुरू कर दिए। हालांकि कोई भी देश किसी भी अन्य देश से रिश्ते सुधारता है तो इसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के साथ हुई मुलाकात में बांग्लादेशी सरकार के मुख्य कर्ता-धर्ता मोहम्मद यूनुस ने 1971 के मसले सुलटाने की बात कही, बांग्लादेशी सेना को पाक सेना के जरिए ट्रेनिंग दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई और बगैर जांच पड़ताल के पाकिस्तानी जहाज व पाक नागरिकों को प्रवेश दिया जाने लगा है, वह सामान्य बात नहीं है। पहले ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बांग्लादेश के जरिये भारत में आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ाने की कोशिश की थी। वह फिर से ऐसी कोशिशें कर सकती है। ऐसे में भारत को बांग्लादेश सीमा को लेकर सतर्कता बढ़ानी होगी।

रोज़-ब-रोज़

नई पीढ़ी की बचत

शैलेंद्र पांडेय

कुछ साल पहले यह बहस शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाती। कम से कम दिसंबर की एक ठंडी शाम पार्क में खड़े होकर तो बात बिल्कुल नहीं होती कि घर किराये का अच्छा या अपना! जिनका अपना घर था, वे भी थोड़ा कंफ्यूज थे कि लेकर सही किया है या गलत। कहीं 20 साल के लिए फंस तो नहीं गए? इतने में तो रिटायरमेंट की उम्र आ जाएगी। और उन्हीं का बेटा उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, 'यही तो पापा, एक किरायेदार की तरह आप भी तो किस भर रहे हैं। हम जितनी EMI दे रहे हैं, हमारे किरायेदार उसका चौथाई भी नहीं देते और वही सुविधाएं उठा रहे हैं, जो हम। बाकी पैसा वे मार्केट में लगा देंगे, तो कहीं ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। उनका जब मन करेगा, वे हमसे अच्छी लोकैलिटी में चले जाएंगे, पर हम तो अब कहीं नहीं जा सकते।' बेटा फंसा है रिटर्न में और बाप इमोशन में। बाप को तसल्ली है कि कम से कम छत हो गई अपनी और बेटे को विरासत में कुछ तो दे पाऊंगा, जबकि बेटे के लिए घर लायबिलिटी है। और इसने यह सब सीखा कहां से? 'यूट्यूब पर देखा है। वहां पूरा कैलकुलेशन करके बताते हैं। मार्केट में पूरा सेफ होकर चलेंगे, तब भी कहीं ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा।'

घर से जुड़ी इमोशनल वैल्यू और इकनॉमिक वैल्यू की बहस को पार्क में ही छोड़ देते हैं, लेकिन यह तस्वीर बताती है कि किस तरह नई पीढ़ी इन्वेस्टमेंट को लेकर जागरूक हो रही है। आर्थिक रूप से 2024 जो भी प्रभाव छोड़कर जाए पर निवेश के मोर्चे पर इसने उसी काम को आगे बढ़ाया है, जो 2023 छोड़कर गया था। पिछले महीने का एक सर्वे बताता है कि मिलेनियल्स और जेनरेशन Z पीढ़ियां रेगुलर सेविंग में यकीन रखती हैं। 22 से 25 साल की उम्र के जो युवा थोड़ा-बहुत भी कमाने लगे हैं, वे एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाकर रखते हैं। और ज्यादातर की पसंद है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड। इस बढ़ती जागरूकता और दिलचस्पी का परिणाम है कि जनवरी में जो म्यूचुअल फंड फोलियो 16.89 करोड़ थे, वे नवंबर में 22 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए। इक्विटी में सबसे ज्यादा फोलियो खुले।

नई पीढ़ी ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को जानकारी हासिल करने का बड़ा जरिया बनाया हुआ है और टेक्नॉलजी ने उसे सहूलियत दी है कि वह अपने फाइनैंस को मैनेज कर सके। नतीजा यह कि जो आंकड़े एक दशक पहले सपने सरीखे थे, वे अब नई पीढ़ी को आसान लगने लगे हैं। इतना कॉन्फिडेंस आ गया है उसमें कि वह दूसरों को सिखाने लगी है कि अपना पैसा कहां लगाएं। अगर बेटे की सलाह मानकर उस पिता ने भी 'म्यूचुअल फंड सही है' को फॉलो कर लिया हो, तो हैरत की बात नहीं।

एकदा

खोज की धुन

महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन उन दिनों अपने आविष्कारों में इतना डूबे रहते थे कि कई बार दिन-दुनिया से कट जाते थे। एक बार वह ट्रेन से प्रिंसटन सिटी से यात्रा पर निकले। कुछ देर बाद टिकट कलेक्टर उनके पास आया। उन्हें देखकर आइंस्टाइन ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला, लेकिन टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अपनी पेंट की जेबें देखीं। वहां भी टिकट नहीं था। उन्होंने अपने साथ लाए गए सामान में भी टिकट खोजा, लेकिन नहीं मिला। इस पर टिकट कलेक्टर बोला, 'सर, रहने दीजिए। मुझे आपका टिकट चेक नहीं करना है। आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं। आपका इस ट्रेन में होना ही हमारे लिए गर्व की बात है।' इतना कहकर टिकट कलेक्टर दूसरे यात्रियों की तरफ बढ़ गया। लेकिन, जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि आइंस्टाइन अब भी पागलों की तरह टिकट ढूंढने में लगे हुए थे। यह देखकर टिकट कलेक्टर उनके पास लौट गया। उसने कहा, 'सर, कृपया अपना काम कीजिए ना।' आइंस्टीन बोले, 'मैं अपना काम ही कर रहा हूं।' टिकट कलेक्टर हैरानी भरी नजरों से बोला, 'सर, मैं समझा नहीं।' आइंस्टाइन बोले, 'अरे भई, दरअसल मैं यह भी भूल गया हूं कि मैं कहां जा रहा हूं? अगर टिकट मिल जाता तो पता चल जाएगा कि मैं कहां और किस काम से निकला था?' उनके इस जवाब पर ट्रेन के अन्य यात्रियों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। लेकिन, टिकट कलेक्टर समझ गया कि आइंस्टाइन के मन-मस्तिष्क में आविष्कार की ऐसी धुन लगी है कि वह अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं।

Subrata Char

संकलन : रेनु सैनी

बाकू का साफ़ संदेश है कि हमारा समाज किसी एक उद्देश्य के लिए मिलकर काम करने लायक नहीं रहा

धरती बचाने के लिए नया प्लान चाहिए

सुनीता नारायण

हम उथल-पुथल भरे दौर में जी रहे हैं। दुनिया भू-राजनीतिक हलचल और संघर्षों में घिरी हुई है। यह वह समय है जब आर्थिक मंदी और ट्रेड वॉर का खतरा लगातार मंडरा रहा है, प्राकृतिक संसाधन तेजी से घट रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। 2024 कई मायनों में दुनिया को बदलने वाला साल साबित हुआ। हर दिन कहीं न कहीं मौसम का कहर टूटा। तापमान के रेकॉर्ड बने और टूटे। जो लोग पहले से ही मुश्किल हालात में जी रहे थे, बार-बार आने वाली आपदाओं ने उन्हें हताश तोड़ दिया कि वे वापस खड़े होने की ताकत भी खो बैठे।

बदलाव का दौर | हम एक नए दौर में कदम रख रहे हैं। वैज्ञानिक इसे Anthropocene युग कहते हैं, जहां इंसानों की गतिविधियों का पृथ्वी की जलवायु और पर्यावरण पर बड़ा असर हो रहा है। यह दौर बड़े बदलाव का है। इंसान के तौर पर हम एक-दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसमें बदलाव आ रहा है। सही और गलत के वैश्विक मानदंड बदल रहे हैं। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की ताकत में बदलाव आ रहा है, जो आने वाले बरसों में लगभग हर चीज को नियंत्रित करेगी।

कंपनियों का नियंत्रण | इन सबमें हमने नए दौर की टेक कंपनियों पर ज्यादा विश्वास किया है। आज की बड़ी टेक कंपनियां किसी बड़े साम्राज्य जैसी हैं, जिनके हाथ में सारा नियंत्रण है। हमारे जीवन का हर पहलू इनसे प्रभावित हो चुका है। इनकी कमान जिनके पास है, वे केवल टेक्नॉलजी या मीडिया ही नहीं, राजनीति में भी बदलाव ला रहे हैं। जैसे-जैसे सरकारें कमजोर हो रही हैं, ये कंपनियां मजबूत होती जा रही हैं।

निजी का बोलबाला | ज्यादातर सरकारों को भ्रम है कि वे नीतियां बना रही हैं और ये जनहित में हैं। सच तो यह है कि सरकारों ने यह काम बड़े कंसल्टेंसी फर्म्स, निवेश बैंकों और निजी कंपनियों को सौंप दिया है। अब सार्वजनिक क्षेत्र निजी हो गया है और हम सब सिर्फ दर्शक बने हुए हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, लेकिन यह सच है कि व्यापार और उपभोक्ता वर्ग के बीच के रिश्ते ने इसे काफी हद तक बदल दिया है।

असुरक्षित दुनिया | आज हमारी दुनिया कहीं अधिक असुरक्षित है। असमानता बढ़ी है। अमीर और अमीर हो गए हैं, जबकि गरीब और भी गरीब। कोविड-19 ने अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया, जिससे पिछले 5 बरसों में असमानता और बढ़ी। जब तक इकॉनमी संभलती, युद्ध छिड़ गए। इसमें खराब गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज और संसाधनों की कमी को जोड़ दीजिए- इससे माइग्रेशन बढ़ा है। ये चीजें गुस्से और असुरक्षा को बढ़ावा देती हैं, जो फिर लोकतंत्र को नफरत और ध्रुवीकरण की बातों का शिकार बना देती हैं।

आक्रोशित जनता | केवल गरीब ही नहीं, अमीर भी ठगा हुए महसूस कर रहे हैं। 1990 के दशक में जब आर्थिक सुधार की कोशिशें हुईं, तो गरीब सबसे ज्यादा चिंतित थे। उन्हें रोजगार छिनने का डर था। मुक्त व्यापार समझौतों के खिलाफ तब किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। आज स्थिति बदल चुकी है। अब नई अर्थव्यवस्था से अमीर देशों के मजदूर बाहर हैं। वे उन 'शिक्षित अभिजात वर्ग और विशेषज्ञों' के खिलाफ हो गए हैं, जिन्होंने इस समाज में जुड़ी दुनिया की सेवा और विलीय अर्थव्यवस्था से फायदा उठाया।

सब पर शक | इस वर्ग संघर्ष का सबसे खराब परिणाम यह है कि विचारों को नकारा जा रहा है। लोग ज्ञान को संदिग्ध और निजी हितों से भरा हुआ मानते हैं। यह उस तरीके का नतीजा है, जिससे हमने दुनिया के इंफॉर्मेशन और विजनेस सिस्टम बनाए हैं। हित की बातों को भी शक की नजरों से देखा जा रहा, जैसे जलवायु परिवर्तन। अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप की वापसी के साथ इनका विरोध भी हो रहा है।

असहयोग की भावना | मौसम से जुड़ी आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए हम पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे। हमारा समाज अब ऐसा नहीं रहा, जो मिलकर किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर सके। बाकू में हुए जलवायु सम्मेलन (COP 29) में अमीर देशों ने दिखावा करना भी छोड़ दिया कि वे दुनिया की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने बस नाम के लिए क्लाइमेट फाइनैंस का वादा किया है। ये अमीर देश, जिन्होंने अतीत में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया, कह रहे हैं कि गरीब देशों को अपनी समस्याएं खुद हल करनी होंगी।

टूट गया भ्रम | जब दुनिया ने आपस में जुड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं की ओर कदम बढ़ाया, तो सोचा गया था कि इससे सभी देश समृद्ध और सुरक्षित हो जाएंगे। माना गया कि देश एक-दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि उनका हित मिलकर काम करने में होगा। लेकिन, उद्योगों को इस वजह से स्थानांतरित किया गया ताकि श्रम और पर्यावरण सुरक्षा की लागत कम की जा सके। इन खर्चों के साथ उत्पादन करना बहुत महंगा था। इस वजह से उद्योग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और साथ में कार्बन इमिशन भी। चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। अब जब दुनिया को ग्रीन एनर्जी चाहिए, तो नई तकनीक सामने आ रही है। हरित उत्पादों का प्रॉडक्शन अब भी 'दूसरी' दुनिया, खासकर चीन में सस्ता है।

सबक सीखना होगा | ट्रंप ने यह वादा किया है कि व्यापार युद्ध शुरू करके अपने देश में कारोबार वापस लाएंगे। लेकिन इससे लागत बढ़ेगी, आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों के लिहाज से। आज की दुनिया व्यापार के मामले में इतनी जुड़ी हुई है कि इसे अलग करना आसान नहीं। यह कदम लो-कार्बन इकॉनमी की दिशा में हो रही प्रगति को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए, हमें भविष्य के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी। यह तय है कि हम पुराने तरीके अपनाकर आगे नहीं बढ़ सकते। हमें एक नए और बेहतर भविष्य के लिए काम करना होगा, लेकिन अपनी गलतियों से सबक लेते हुए।

(लेखिका Centre for Science and Environment की डायरेक्टर जनरल हैं)

कैसा रहा 2024

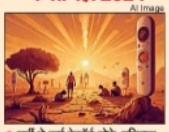

- गर्मी ने कई रेकॉर्ड तोड़े, इतिहास का सबसे गर्म साल
- औसत वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हुआ
- अजरबैजान के बाकू में कॉप-29 असहमति के बीच खत्म
- विकसित देशों का उम्मीद के मुताबिक मदद से इनकार
- भारत में पहले 9 महीनों के 93% दिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन

2025 की तस्वीर

- कॉप 30 ब्राजील के Belem में होगा, नए लक्ष्य रखे जाएंगे
- ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के नए टारगेट तय करने होंगे
- ट्रंप की वापसी से कमजोर हो सकती है पर्यावरण की लड़ाई
- भारत ने 3.5 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य रखा
- एयर पलूशन के खिलाफ नैशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पर नजर

हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स क्यों कर रहे स्यूसाइड

गणेश कोहली

साल 2022 में देश में स्टूडेंट्स स्यूसाइड के 13,044 मामले दर्ज किए गए। पिछले दशक में यह आंकड़ा 6,654 था। 35% मामले तो केवल तीन राज्यों- महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से सामने आए। महाराष्ट्र 14% के साथ सबसे आगे रहा। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य यूपी 2022 में 8% स्टूडेंट्स स्यूसाइड के साथ चौथे नंबर पर था। ये आंकड़े डराने वाले हैं।

खतरनाक आंकड़े | देश में कुल आत्महत्या का जो एवरेज रेट है, उसके मुकाबले स्टूडेंट्स स्यूसाइड के केस बहुत तेजी से बढ़े हैं। IC3 इंस्टिट्यूट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 से 2022 के बीच 18 से 23 साल के लगभग 6% छात्रों और 7% छात्राओं ने आत्महत्या की। पिछले 10 बरसों में छात्रों में आत्महत्या की दर 99%, जबकि छात्राओं में 92% बढ़ी है। यह खलल ट्रेड के विपरीत है, जहां आमतौर पर लड़कों के स्यूसाइड करने की दर अधिक होती है।

सामाजिक समस्या | देश में कुल जितने स्यूसाइड होते हैं, उनमें 7.6% हिस्सा स्टूडेंट्स का है। हम किसानों की आत्महत्या के बारे में सुनते हैं लेकिन, स्टूडेंट्स भी अब इसी कैटिगरी में आ चुके हैं और उन पर भी वैसा ही खतरा मंडरा रहा है।

जीवन पर भारी उम्मीदें | स्टूडेंट्स स्यूसाइड का एक बड़ा कारण है उन पर पड़ने वाला दबाव, खासकर पढ़ाई से जुड़ी उम्मीदों का बोझ।

मेंटल हेल्थ | कई छात्र असफलता के डर से जूझते रहते हैं। यह समस्या और बढ़ जाती है क्योंकि हमारे स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। काउंसिलिंग की कमी भी एक बड़ी समस्या है।

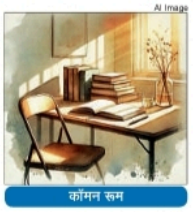
कॉमन रूम

कुछ सुझाव | स्टूडेंट्स को संकट से निकालने के लिए ये कुछ उपाय किए जा सकते हैं :

- मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों के लिए शिक्षकों के पास ट्रेनिंग और रिसोर्स नहीं होते। उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे वे पहचान सके कि कौन-सा स्टूडेंट परेशानी में है और उसकी कैसे मदद की जा सकती है।
- शैक्षिक संस्थानों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, जिसमें शैक्षिक सफलता से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य को महत्व दिया जाए।
- माइंडफुलनेस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसी चीजों पर ध्यान दिया जाए।
- नैशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) और UMEED की गाइडलाइंस में मेंटल हेल्थ को महत्व दिया गया है। हालांकि असली चुनौती है नीतियों को सही ढंग से लागू करना।

स्टूडेंट्स स्यूसाइड की बढ़ती संख्या केवल आंकड़ा नहीं। यह एजुकेशनल और सोशल सिस्टम की विफलता को दिखाता है। हमें ऐसे काम करना होगा, जिससे स्टूडेंट्स को बेहतर मदद मिले और मेंटल हेल्थ से जुड़ी शर्म को खत्म किया जा सके।

इस्तीफा अच्छा या बुरा

बीते दिनों केंद्र सरकार ने कुछ नए राज्यपाल बनाए। जिन नए लोगों को राज्यपाल बनाया गया, उनमें अधिकतर के नामों की पहले से ही चर्चा थी। हैरानी तो ओडिशा के गवर्नर रहे रघुवर दास के इस्तीफे को लेकर हुई। उन्होंने जैसे ही इस्तीफा दिया, उसके बाद से BJP के अंदर चर्चा का नया दौर शुरू हो गया है। दरअसल पार्टी में नए साल की शुरुआत में 14 जनवरी के बाद संगठन स्तर पर कई बड़े बदलाव होने हैं। पार्टी नया अध्यक्ष भी चुनने वाली है। ऐसे में रघुवर दास के समर्थक अभी तक यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस्तीफा अच्छी खबर है या निराश करने वाली? संगठन में फेरबदल के बीच झारखंड में भी BJP नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाली है। पार्टी के एक सीनियर नेता ने कहा कि यहां हमेशा चौंकाने वाले फैसले होते हैं, ऐसे में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। रघुवर दास के पक्ष में उनके समर्थकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले नारे भी लगाए। लेकिन उन्हें किसी ने समझाया कि यहां फैसला होने से पहले जो भी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करता है, उसके साथ ठीक उलटा होता है। दरअसल पार्टी में नए अध्यक्ष के साथ ही संगठन में अहम पदों को लेकर कई नामों की चर्चा चल रही है। संगठन में फेबरदल के बाद पार्टी के समीकरणों में भी बड़े बदलाव होने की संभावना बताई जा रही है।

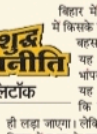

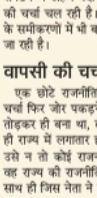

वापसी की चर्चा

एक छोटे राजनीतिक दल के कांग्रेस में विलय की चर्चा फिर जोर पकड़ने लगी है। यह क्षेत्रीय दल कांग्रेस तोड़कर ही बना था, लेकिन पिछले कुछ सालों से अपने ही राज्य में लगातार हाशिए पर पड़ा रहा। इस वक्के में उसे न तो कोई राजनीतिक सफलता मिली और न ही वह राज्य की राजनीति में कोई खास असर डाल पाया। साथ ही जिस नेता ने कांग्रेस छोड़कर पार्टी बनाई, उनके निधन होने का भी असर पार्टी पर पड़ा। अब उनके बेटे खुद के लिए नई संभावना की तलाश में हैं। इसी क्रम में उन्हें करीबियों ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में दोबारा विलय करने का प्रस्ताव दे डाला। उनके प्रस्ताव पर कांग्रेस में दो तरह की राय है। एक वर्ग उनकी पार्टी के विलय के पक्ष में है, लेकिन दूसरे को इस पर आपत्ति है। दूसरे वर्ग का मानना है कि इनके पार्टी में आने से यहां का अंदरूनी समीकरण प्रभावित हो सकता है और अब उनकी कोई जरूरत भी नहीं है। बात पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची है। बात आगे बढ़ाई जाए या नहीं, इसकी हरी झंडी मिलने के बाद ही अब इसमें कोई प्रगति होगी। लेकिन पार्टी नेतृत्व ने अभी तक इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया है। कहा जा रहा है कि बेंगलुरु अधिवेशन के बाद दिल्ली में इस मसले पर सभी पक्षों के साथ मंथन हो सकता है।

बयान पर बयान

बिहार में अगला विधानसभा चुनाव NDA में किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, अभी इस पर बहस ही चल रही थी। मगर JDU को यह बहस नागवार गुजरी। उसका मूड भांपकर BJP ने दिल्ली से पटना तक यह बात साफ करने का प्रयास किया कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही हर स्तर पर सफाई आई, बिहार में BJP के एक सीनियर नेता ने यह कहकर बहस को फिर से जारी कर दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक बिहार में अपने दम पर BJP की सरकार न बन जाए। अब JDU इस बयान पर सफाई मांग रही है।

सोशल मीडिया पोस्ट के मायने

BJP अमूमन अनुशासित पार्टी रही है। यहां पार्टी का कोई नेता तय लाइन के इतर कम ही बोलता है। ऐसे में पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का अपनी ही सरकार पर सवाल उठाना हैरान कर गया। उन्होंने परोक्ष रूप से सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाया और मिडिल क्लास को राहत देने की मांग की। इससे भी हैरानी भरी बात यह रही कि उनकी सोशल मीडिया पोस्ट विवादित होने के बाद भी डिलीट नहीं हुई और न ही उनकी ओर से इस पर कोई सफाई दी गई। तब से कई तरह की चर्चाएं उठने लगीं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से NDA सरकार की आर्थिक नीतियों, खासकर टैक्स सिस्टम को लेकर सोशल मीडिया में कई सवाल उठ रहे हैं। तरह-तरह के मीम भी बने हैं। इससे सरकार और पार्टी के अंदर चिंता भी बताई जा रही है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि जल्द ही इस मोर्चे पर पार्टी कुछ बड़ी राहत का एलान कर सकती है और इसके लिए अभी से माहौल बनाने की कवायद है। लेकिन अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने की बात को लेकर पार्टी के अंदर कई तरह की चर्चा है। क्योंकि यहां ऐसा विरले ही होता रहा है।

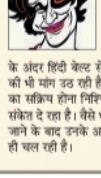

सक्रियता की चर्चा

बेंगलुरु में कांग्रेस अधिवेशन से पहले पार्टी सांसद प्रियंका गांधी की सक्रियता खासी चर्चा में रही। उन्होंने न सिर्फ मीटिंग के अजेंडे को अंतिम रूप देने में सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि संगठन के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में भी सक्रिय रहीं। इसके बाद उनकी अगली भूमिका को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है। हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी को मिली हार के बाद अब संगठन में बड़ा बदलाव लाने का दबाव पार्टी नेतृत्व के ऊपर है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी कई लोगों के टारगेट पर हैं। पार्टी के अंदर हिंदी बेल्ट से किसी नेता को अहम भूमिका देने की भी मांग उठ रही है। इन चर्चाओं के बीच प्रियंका गांधी का सक्रिय होना निश्चित ही किसी बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। वैसे भी वायनाड से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद उनके अगले कदम के बारे में चर्चा पहले से ही चल रही है।

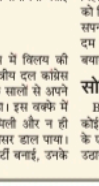

पॉलिटॉक

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ चिंता की बात

26 दिसंबर का लेख 'NTA का बोझ कम होगा, पर दुश्वारियां नहीं' पढ़ा। नैशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली हाल के वर्षों में सवालों के घेरे में रही है, खासकर 2024 के NEET में गड़बड़ियों के बाद। NTA की अधिकांश परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड होती हैं, जिससे कई सेंटरों से गड़बड़ी की खबरें आती हैं। यह स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए चिंता का विषय है। NEET जैसी परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला और भी चिंताजनक है। कमिटी का कहना है कि हर जिले में टेस्टिंग सेंटर उपलब्ध हों, लेकिन इसके लिए बड़ी संख्या में प्राइवेट सेंटरों की आवश्यकता होगी। हालांकि, स्थानीय प्रशासन की मदद से सारी मुश्किलों को दूर किया जा सकता है।

कार्तिक त्यागी, ईमेल से

■ विरोध राजनीतिक

यह पत्र 25 दिसंबर के लेख 'एक साथ चुनाव का इतना विरोध क्यों' से संबंधित है। पीएम मोदी काफी पहले से 'एक देश, एक चुनाव' की बात कहते आ रहे हैं और निश्चित रूप से यह देश के हित में है। इससे देश का पैसा तो बचेगा ही, साथ ही प्रशासन की नाहक भागदौड़ के साथ ही नेताओं की हाय-तौबा में भी कमी आएगी। आजादी के बाद कई साल तक सारे चुनाव एक साथ बिना किसी परेशानी के होते रहे हैं। लेखक ने ठीक कहा कि विरोध केवल राजनैतिक स्वार्थवश न हो।

इन्द्र सिंह धिगान, किंग्जवे कैंप

■ असुरक्षा का माहौल

पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाने और डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी करने के मामले तेजी से बढ़े हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने से जनजीवन में खलल पहुंचा स्वाभाविक है। आधुनिक तकनीक नई-नई सुविधाएं लेकर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। इन सबको रोकने के लिए साइबर सेल है, लेकिन एक्शन होने में इतनी देर लग जाती है कि पीड़ित निराश हो जाते हैं।

शकुंतला नेनावा, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

BJD ने सुनाया चुनावी मे गड़बड़ी का राग – एक खबर

– यह राग अब राग नहीं, हर चुनाव के बाद की आवाज है।

चंदन झा

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

पुण्य की पूंजी बढ़े तो चार्ज होगी ख़ुशियों की बैटरी

ब्रह्मा कुमारी शिवानी

सदा सुख देने और सुख लेने का अभ्यास, न दुख देने और न दुख लेने का अभ्यास हमारे जीवन को खुशहाल बना सकता है। हमारे मन में हमेशा श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए, बुद्धि में सुखद विचार, वाणी में मधुरता, और वृत्ति में शुभ भावनाएं। शुद्ध कामना और कर्मों के साथ सेवा भाव रखना आवश्यक है। हमारे संकल्पों का प्रभाव न केवल हमारे जीवन, बल्कि हमारे परिवार और समाज पर भी पड़ता है।

हमारे शक्तिशाली संकल्प किसी कमजोर आत्मा को भी सशक्त बना सकते हैं और उसके जीवन में उमंग, उत्साह और खुशियां भर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम मन में किसी के लिए भी गांठें न बनाएं, क्योंकि इससे हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है। हर सुबह उठते ही हमें ईश्वर को याद करना चाहिए और उनसे शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। जीवन की सुंदरता और विशेषताओं को देखने के साथ हमेशा सकारात्मक और आशावादी रहना चाहिए। परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अपने शरीर, कर्म, संस्कार, भाग्य और संबंधियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए।

जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, हमें उसमें भी अपना कल्याण देखना चाहिए। हमारी उच्च मानसिक स्थिति विपरीत परिस्थितियों को बदल सकती है और जीवन को खुशियों से भर सकती है। श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उन्हें श्रेष्ठ बनाना चाहिए और नेक कर्मों से पहले अपनी नियत और संकल्पों को कल्याणकारी बनाना चाहिए। इस तरह हम दुआएं कमाएंगे, जिससे पुण्य की पूंजी बढ़ेगी और अंतरात्मा की बैटरी खुशियों से चार्ज होगी। समय का सही उपयोग करके हमें जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहिए। दूसरों को क्षमा करना और स्वयं को भी क्षमा करना जीवन को आसान और संतुलित बना सकता है।

जैसे संकल्पों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, वैसे ही आहार का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। जो हम पढ़ते, सुनते और देखते हैं, वह हमारे जीवन पर असर डालता है, खासकर बच्चों पर इसका प्रभाव अधिक होता है। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के नियमित अभ्यास से हम अपनी अंतरात्मा की शक्तियों को शुद्ध, श्रेष्ठ और सुखदायी बना सकते हैं। मानसिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए, निंदा, स्तुति, जय-पराजय जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विचारों को स्थिर रखना चाहिए। यही मानसिक शक्ति हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाती है। हम अपने तन, मन, धन और जीवन को समृद्ध रख सकते हैं और कई प्रकार के रोगों, शोकों और कष्टों से बच सकते हैं। पवित्र प्रेरणा, दैवी संस्कार और उमंग से भरकर हम अपने जीवन को उत्सव जैसा बना सकते हैं, और हर पल को आनंद से जी सकते हैं।

दैनिक जागरण
आदतें जंजीर की तरह हमें बांध कर रखती हैं

धार्मिक स्थलों का सच

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों के निकट समझे जाने वाले ऑर्गेनाइजर आर्गनाइजर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के हर जगह मंदिर न खोजें वाले कथन से असहमति जताकर इस बहस को और तेज करने का काम किया है कि विवादित धार्मिक स्थलों पर क्या नीति होनी चाहिए? यह बहस तभी छिड़ गई थी, जब कुछ हिंदू संतों ने संघ प्रमुख के बयान को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। इन संतों का कहना था कि विवादित धार्मिक स्थलों का सच जानना आवश्यक है। यही बात अब आर्गनाइजर ने भी कह दी। मोहन भागवत ने करीब दो वर्ष पहले भी यह कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजा जाना चाहिए, लेकिन तब असहमति के ऐसे स्वर नहीं उठे थे, जैसे अब उठे हैं। इसका कारण शायद यह है कि हाल में अदालतों ने कई विवादित धार्मिक स्थलों के सर्वे के आदेश दिए हैं। काशी एवं धार में तो सर्वे हो भी चुका है और मथुरा में ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मांग की जा रही है। संभल में सर्वे के दौरान हिंसा के बाद से मंदिर-मस्जिद से जुड़े कुछ और विवाद सतह पर आ गए। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विवादित धार्मिक स्थलों के सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी। पता नहीं उसका अंतिम निर्णय क्या होगा, लेकिन वह तय है कि मंदिर-मस्जिद से जुड़े विवाद ऐसे किसी आदेश-निर्देश से सुलझने वाले नहीं कि उनकी सच्चाई जानने की जरूरत नहीं या फिर वे 1947 वाली स्थिति में बनाए रखे जाएं। ऐसा होने के आसार इसलिए नहीं, क्योंकि कई प्रमुख धार्मिक स्थल इसकी गवाही दे रहे हैं कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई।

प्रश्न यह है कि मंदिर-मस्जिद विवादों को सुलझाया कैसे जाए? उचित यह होगा कि अतीत के घावों पर मरहम लगाने के लिए अन्य देशों की तरह ट्रुथ एंड रिकंसलिएशन कमीशन जैसा कोई तंत्र बनाया जाए। वह यह पता लगाए कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनाए जाने के दावों का सच क्या है? जो भी सच हो, उसे स्वीकृत और अंकित किया जाए। यह सच जानने का यह मतलब नहीं हो सकता कि देश भर में मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हर मस्जिद को हटाने की मांग की जाए, क्योंकि यह भी समय की मांग है कि देश मंदिर-मस्जिद विवाद से आगे बढ़े। संभवतः मोहन भागवत के कहने का आशय यही है। जो भी हो, यह अपेक्षा भी ठीक नहीं होगी कि हिंदू समाज मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों से तब भी अपना दावा छोड़ दे, जब यह सच सामने आ जाए कि वहां पहले मंदिर ही था। अच्छा यह होगा कि पूजास्थल अधिनियम के प्रविधानों पर विचार कर रहा सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था दे, जिससे धार्मिक स्थलों का विवाद शांति से सुलझे।

विवादों में निकाय चुनाव

हरियाणा में होने वाले नगर निकाय चुनाव विवाद में फंसते दिखाई दे रहे हैं। समय पर चुनाव न होने से पहले से ही विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे, अब जनसंख्या विवाद के कारण देरी होने की पूरी आशंका बन गई है। इसमें और विलंब राज्य तथा राज्य के लोगों के लिए ठीक नहीं है। पहले से तय काम समय पर होना चाहिए। वास्तव में राज्य सरकार भले ही समय पर चुनाव कराने के प्रति गंभीर नजर आ रही है, लेकिन निर्धारित नियमों के कारण पेच फंसता दिखाई दे रहा है। नियमानुसार नगर निगम बनाने के लिए तीन लाख आबादी होना जरूरी है, लेकिन मानेसर की आबादी इससे आधी है। इसके चलते अब इसके अस्तित्व पर सवाल उठना स्वाभाविक ही है। विपक्ष भी सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठा चुका है और बयानबाजी का दौर भी खूब चला। जनसंख्या संबंधी शिकायत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्थानीय निकाय विभाग में पहुंचने के बाद मामला पेचीदा हो गया है। राज्य में दस नगर निगम हैं। इनमें से कई में मेयर नहीं हैं और कई में समय पर चुनाव न होने के कारण वह पद छोड़ चुके हैं। इसमें कोई दोराय नहीं कि मेयर और पार्षद न होने के कारण वार्डों में विकास कार्य उतनी गति से नहीं हो पा रहे, जितनी तेजी की आवश्यकता है। वार्ड प्रतिनिधि के बिना क्षेत्र की समस्याएं उठाने के लिए उपयुक्त मंच नहीं होने से विकास कार्यों पर असर पड़ना चिंता बढ़ाने वाला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल के आगमन के साथ ही चुनाव की घोषणा होने की पूरी संभावना है। राजनीतिक दल भी अपने-अपने स्तर पर तैयारी में लगे हैं।

नए नगर निगम मानेसर की जनसंख्या नियमों के अनुरूप न होने से चुनाव में देरी की आशंका

विशेषाधिकार न मिलने की छटपटाहट

सुरेंद्र किशोर

नेहरू-गांधी परिवार की समस्या यह है कि वह अपने को अदालतों और कानून से ऊपर मानता है

लाख कोशिश के बावजूद गांधी परिवार अपनी कानूनी परेशानियों से बाहर निकल नहीं पा रहा है। 2014 के बाद से ही उसके लिए यह स्थिति पैदा हुई है। उसे अदालतों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। आजादी के तत्काल बाद से ही नेहरू-गांधी परिवार कानून से ऊपर माना जाता रहा। तरह-तरह की कानूनी परेशानियों से यह परिवार साफ बच निकलता रहा, पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस स्थिति को बदल कर रख दिया है। इसी कारण गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड मामले की गिरफ्त में है। नतीजतन गांधी परिवार में अजीब तरह की बेचैनी है। उसका असर राहुल गांधी की देह-भाषा पर है और उनकी जुबान पर भी। राहुल गांधी और उनके लोग कभी चुनाव आयोग तो कभी अदालत के खिलाफ बोलते हैं और कभी संसद के पीठासीन पदाधिकारियों को अपमानित करते हैं। इससे उन्हें कोई राजनीतिक या चुनावी लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन वे समझने को तैयार नहीं। राहुल गांधी यह समझते हैं कि मोदी तथा संवैधानिक संस्थाओं पर भी तरह-तरह के झूठे आरोप लगाकर उन्हें अपने स्तर पर नीचे खींच लाएंगे, ताकि आम लोग मोदी को उनसे बेहतर न मानें, पर ऐसा तो तब होगा जब प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण हाथ लगे। राहुल गांधी को हवा में तीर चलाने से अब तक तो कोई लाभ नहीं मिला है। उल्टे विपक्षी गठबंधन के अधिकतर दलों ने उन्हें एक विफल नेता मानकर उनसे किनारा करना शुरू कर दिया है।

नेहरू-गांधी परिवार में 2014 तक यह धारणा बनी हुई थी कि यह परिवार किसी भी कानून से ऊपर है। भारत उसकी मिल्कियत है। उसे ही इस देश पर शासन करने का नैसर्गिक अधिकार है। मोदी के सत्तासीन हो जाने के बाद परिवार का वह विशेषाधिकार समाप्त हो गया है। नेहरू-गांधी परिवार कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत वाली व्यावहारिक स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो पा रहा है। सोनिया-राहुल की छटपटाहट का सबसे बड़ा कारण यही है। इससे पहले इस परिवार को इतनी छूट रही कि एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कहा करते थे कि ''प्रथम परिवार'' को छूना तक नहीं है। ऐसे अघोषित विशेषाधिकार प्राप्त परिवार के सामने जब कानूनी गिरफ्त से बचने का कोई तरीका नजर न आए तो उसकी मनोदशा कैसी होगी, इसकी कल्पना कर लीजिए। इस तनाव और छटपटाहट के कारण ही राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका भी गरिमापूर्ण ढंग से निभाने में विफल हैं।

अवधेश राजपूत

यदि प्रतिपक्ष का नेता विवेकपूर्ण ढंग से ठोस तथ्यों पर आधारित अपनी बातें रखे तो जनता के बीच उसकी लोकप्रियता बढ़े, छवि बेहतर हो, पर राहुल गांधी ने अपनी असंगत बोली तथा असभ्यान्य हेय भाषा के जरिये सदन की गरिमा गिराने की जितनी कोशिश की, वह अभूतपूर्व है। अपने परिवार के इतिहास के गर्भ में पल रहे राहुल गांधी ने पूर्वजों के इतिहास के किस्से सुन रखे होंगे। संभवतः अपने प्रति उसी तरह के व्यवहार की उम्मीद वह मौजूदा सरकार से भी कर रहे होंगे। अब यह संभव नहीं।

गांधी परिवार पर पहला कानूनी संकट नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही आया था। 1949 में लंदन में भारतीय उच्चायुक्त वीके कृष्णामेनन पर जीप घोटाले का गंभीर आरोप लगा। कांग्रेसी नेता अनंत शयनम अयंगार की जांच कमेटी ने उन्हें सरसरी तौर पर दोषी माना और विस्तृत न्यायिक जांच की सिफारिश की। न्यायिक जांच के परिणामस्वरूप सरकार के खिलाफ कुछ असुविधाजनक जानकारियां सामने आने का खतरा दिखा। इसलिए तत्कालीन गृह मंत्री ने 30 सितंबर, 1955 को लोकसभा में यह घोषणा कर दी कि जीप घोटाले के इस मामले को बंद कर दिया गया है।

1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया था तो यह आरोप साबित हो गया था कि चुनाव में उन्होंने सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया है। कोई अन्य उपाय न देखते हुए इंदिरा ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी और चुनाव कानून बदल दिया। इस तरह उनकी सदस्यता और गद्दी दोनों बच गईं। एक अन्य तरह के जीप घोटाले के सिलसिले में तीन अक्तूबर, 1977 को सीबीआइ ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर अगले दिन दिल्ली के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया। मजिस्ट्रेट ने सुबूत मांगे तो सीबीआइ के वकील ने कहा कि जांच हो रही है। मजिस्ट्रेट ने श्रीमती गांधी को रिहा करने का आदेश दे दिया। 1979 में जनता पार्टी में आंतरिक कलह के कारण मोरारजी देसाई सरकार गिर गई। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देकर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को संदेश भेजा कि आप संजय गांधी के खिलाफ जारी मुकदमे को वापस ले लें। चौधरी चरण सिंह ने इन्कार किया तो उनकी सरकार गिरा दी गई। 1980 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी सत्ता में लौटीं। फिर कौन मुकदमा और कैसी जांच? सब कुछ समाप्त हो गया।

जब 1990 में कांग्रेस के बाहरी समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी ने उन्हें संदेश भेजा कि बोफोर्स केस वापस कर लीजिए। ऐसा करने से मना करते हुए चंद्रशेखर ने इसीलिए दे दिया गत दिनों खबर आई कि बोफोर्स मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। ज्ञात हो कि 2004 में बोफोर्स मामले में राजीव गांधी और संबंधित दलाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई थी। हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए सीबीआइ को अनुमति नहीं दी गई थी, जबकि एजेंसी के ला अफसर ने अपील के लिए इसे एक मजबूत मामला बताया था। नेहरू-गांधी परिवार की समस्या यह है कि सरकार तथा संवैधानिक संस्थानों पर ओछे आरोपों और टिप्पणियों के बाबजूद प्रधानमंत्री मोदी इस परिवार को कानून से ऊपर नहीं मान रहे हैं। इसी कारण यह परिवार उन पर अनावश्यक रूप से हमलावर रहता है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

गंभीर संकट का कामचलाऊ समाधान

पंकज चतुर्वेदी

अभीन फरालीजल रही, न आतिशबाजी हो रही है, फिर भी दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है

वह तो भला हो प्रकृति का कि दिसंबर के अंतिम दिनों में दिल्ली-एनसीआर में थोड़ी सी बारिश हो गई, वरना राजधानी क्षेत्र की कोई चार करोड़ आबादी लगभग जहर को सांसों के जरिये अपने शरीर में उतार रही थी। इससे पहले ग्रेप की कई पाबंदियां लागू होने के बावजूद दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) साढ़े चार सौ के पार था। अभी न शहर में ट्रक आ रहे, न निर्माण कार्य चल रहा, न हरियाणा-पंजाब में पराली जल रही, न ही कहीं आतिशबाजी हो रही है। इसके बावजूद दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर श्रेणी में होना दर्शाता है कि सरकार में बैठे लोग या तो वायु प्रदूषण के असल मर्ज को पकड़ नहीं पा रहे या फिर कोई ईमानदारी से इसका निदान नहीं चाहता। दिल्ली-एनसीआर के अधिकतर इलाकों में एक्यूआइ लेवल करीब 300 है। इस बार तो ठंड शुरू होने से बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने वायु को जहर होने से रोकने की कार्य योजना मांगी थी। अफसोस कि सरकार में बैठे लोग इंसान से उपजी दिक्कतों का हल मशीनों में खोजने का असफल प्रयोग करते रहे, जबकि जहरीली हवा यहां के लोगों की जिंदगी के साल काम कर रही है। वह छोटे बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रही है। इससे समाज और सरकार, दोनों पर भारी आर्थिक नुकसान भी भार पड़ रहा है।

जब दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर रोक नहीं लगाई जा पा रही, तब यह सहज ही समझा जा सकता है कि शेष उत्तर भारत में प्रदूषण रोकने के लिए कुछ ठोस नहीं किया जा रहा होगा। दिल्ली जैसे महानगरों की त्रासदी है कि वे किसी भी समस्या के लिए पड़ोसी को दोषी बताने को तत्पर रहते हैं और अपनी आदतों एवं प्रकृति-हंता कृत्यों को कभी मजबूरी तो कभी हक के साथ स्वीकार नहीं करते। यह बात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फिर से कही है कि दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य स्रोत वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन है, जिसका अति सूक्ष्म कण (पीएम) 2.5 में भागीदारी 18.8 प्रतिशत है। दुर्भाग्य यह है कि सभी जानते हैं कि दिल्ली की हवा को खराब करने में सबसे बड़ी भूमिका वाहनों से निकले धुएं और खासकर सड़कों पर लगने वाले जाम की है, लेकिन समूचा तंत्र इस विषय में पूरी तरह गैर संवेदनशील है। इसके बावजूद वाहनों के परिचालन में सख्ती के लिए न निजासी तैयार हैं, न वाहन बेचने एवं कर्ज देने वाली वित्तीय संस्थाएं और न ही पेट्रोल-डीजल बेचने वाली लाबी। वाहनों के उत्सर्जन में नाइट्रोजन आक्साइड गैस भी होती है, जिसके कारण वायु प्रदूषण गंभीर होता जाता है। हमें समझना होगा कि वाहन चलने से केवल ईंधन उत्सर्जन ही हवा को जहर नहीं बनाता, बल्कि वाहन में लगी बैटरी से निकलने वाले अम्लीय अदृश्य धुएं और टायरों के सड़क से घर्षण से उत्पन्न बहुत बारीक स्वर कण भी कम जानलेवा नहीं होते।

प्रदूषण की रोकथाम के आधे-अधूरे उपाय। एएनआइ

पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने दफ्तर और स्कूल के समय में बदलाव करने का प्रयोग किया था, लेकिन वह अंतराल महज आधे घंटे का था, लिहाजा उसका कोई असर परिवहन पर नहीं पड़ा। कई बार तो लगता है कि सरकार में बैठे लोग इंसानों की जान बचाने से अधिक अदालतों के सामने अपनी खाल बचाने के लिए गैरजरूरी प्रयोग कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेते हैं। बायुमंडलीय और मौसम की स्थितियां वायु में प्रदूषण के स्तर पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। हवा की गुणवत्ता खराब होने के दो ही बड़े कारण हैं-हाइड्रोकार्बन और धूल। हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन या तो औद्योगिक गतिविधियों से होता है या फिर आटोमोबाइल के धुएं से। पक्की सड़कों वाले शहर में धूल कण का आगम भी यातायात की हलचल ही है। थोड़ा मौसम नम हुआ, ओस गिरी तो यही दोनों प्रदूषकों का संयोजन अक्सर स्माग यानी धुंध पैदा कर देता है और वही जानलेवा होता है। जब तापमान गिरता है और ठंडी हवा जमीन को ढक लेती है, तो किसी भी गर्म हवा को इसके ऊपर से गुजरना पड़ता है। इस तरह प्रदूषक कण धनी ठंडी हवा में कहीं फैल नहीं पाते हैं। इस प्रकार धूल और जहरीले कणों वाली हवा पूरे परिवेश को ढक लेती है। चूंकि ठंडी हवा अधिक घनी होती है और धीमी गति से बहती है, इसीलिए दूषित हवा के हमारी सांसों में बस जाने और उसके गंभीर परिणाम होने की आशंका ठंड और ओस के दिनों में सर्वाधिक होती है। यदि विज्ञान के इसी सिद्धांत के मुताबिक दिल्ली में सतर्कता बरती जाए और प्रदूषण नियंत्रण की योजना बने तो इस संकट को काफी कुछ कम किया जा सकता है।

सड़कों पर भीड़ कम करने के लिए खराब वाहनों को सड़क पर आने से रोकने जैसे तात्कालिक उपाय तो ठीक हैं, लेकिन इसके लिए कुछ दूरगामी उपाय भी करने होंगे, जैसे गैरजरूरी कार्यालयों को दिल्ली-एनसीआर से दूर भेजना होगा। बस स्टैंड की मौजूदा व्यवस्था में सुधार और रिंग रेलवे को मजबूत करना होगा। अलग-अलग सड़कों पर विभिन्न गति वाले वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगानी होगी। आवासीय इलाकों में बाजार बनाने से रोकना होगा। साथ ही गंभीर दिनों में हर तरह के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि आयोजनों पर रोक लगानी होगा, जो सड़क घेरते हों या जाम पैदा करते हैं।

(लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

अंधकार से प्रकाश की ओर

बृहदारण्यक उपनिषद का एक श्लोक है, 'असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय।' इसका अर्थ है मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, क्योंकि अंधकार और अज्ञान यूवत जीवन मृत्यु के समान है। मानव जीवन को असत्य, अनाचार, अविवेक जैसे अनेकों प्रकार के अंधकारों का ग्रहण लगा रहता है। वह इनमें उलझकर जीवन की सार्थकता भूल जाता है। जब कभी समझ में आता है तब तक बहुत विलंब हो चुका होता है। ईश्वर प्रदत्त इस जीवन रूपी उपहार का कोई जनकल्याणकारी उपयोग नहीं कर पाता है।

काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार जैसे अनेक प्रकार के अंधेरे जीवन को प्रकाश की ओर बढ़ने में बाधक बनते हैं। इनसे मुक्ति की प्रार्थना के बजाय प्रायः मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, इसी के लिए चेष्टारत रहता है। उसकी प्रार्थना में 'हे प्रभु आनंद-दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को, दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बनें, ब्रह्मचारी धर्म-रक्षक, वीर व्रत धारी बनें।' जैसी सगुणी प्रार्थना के बजाय अन्य सभी सांसारिक इच्छा पूर्ति का समावेश ही मिलता है। सरल जीवन जीने और निर्मल मन मिलने की कामना का सर्वथा अभाव उसकी प्रार्थना में होता, किंतु सांसारिक सभी सुखापभोग की इच्छा वह अवश्य करता है। लोगों को एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि छल-छिद्र रहित कर्म से ही हम प्रभु के स्नेह के पात्र हो सकते हैं। इस राह के बाधक बने अंधेरे और अज्ञानता के फेरे मनुष्य की जड़ता समाप्त कर उसमें चैतन्यता जागृत हो नहीं होने देते। तमसो मा ज्योतिर्गमय के भावों से हमें न केवल सांसारिक कामनाओं से निवृत्ति मिलेगी, वरन ज्ञानोदय होने से मन की आंखें भी खुलेंगी।

एसएन दुबे 'स्नेही'

बच्चों की बेहतरी से जुड़ा निर्णय

डा. मोनिका शर्मा

सरकार द्वारा जारी नए नियमों के तहत अब पांचवीं और आठवीं की परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थियों को सफल घोषित नहीं किया जाएगा

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 'नो डिटेंशन पालिसी' समाप्त करने का निर्णय लिया गया। ध्यातव्य है कि इस नीति के अनुसार फेल होने के बावजूद विद्यार्थी अगली कक्षा में पहुंच जाते थे। नए नियमों के तहत अब 5वीं और 8वीं की परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थियों को सफल घोषित नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार फेल होने वाले बच्चों को दो महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। दोबारा परीक्षा देकर भी पास न हो पाने वाले बच्चों को आगे की कक्षा में नहीं भेजा जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को उसी कक्षा में फिर पढ़ना होगा। हालांकि नए नियमों के साथ सरकार द्वारा यह प्रविधान भी जोड़ा गया है कि 8वीं तक के ऐसे बच्चों को विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा।

दरअसल यह निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने से जुड़ा है। शुरुआती पड़ाव पर ही देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के पठन-पाठन की नींव को मजबूती देने वाला है। सहजता से अगली कक्षा में पहुंचने की नीति असल में पढ़ाई के मोर्चे पर बच्चों की बुनियाद कमजोर करने वाली साबित हुई। ज्ञात हो कि वर्ष 2009 में विद्यालयों में नो डिटेंशन पालिसी की शुरुआत हुई थी। इस नीति के तहत कक्षा आठ तक के बच्चों को फेल होने के बावजूद आगे की क्लास में भेजने का का प्रविधान किया था। वर्ष 2019 में राइट टू एजुकेशन एक्ट में संशोधन कर इसे बदलने पर विचार किया। हालिया निर्णय इसी बदलाव को धरातल पर उतारने की कवायद है, जिसका सीधा संबंध शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी और विद्यार्थियों में सीखने-समझने के रुझान को कायम रखना है।

विचारणीय है कि राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूलों में बच्चों का नामांकन तो बढ़ा, पर शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई। बालमन शिक्षा के प्रति गंभीरता से दूर हुआ। बच्चों में कठिन विषयों को समझने के प्रयासों और श्रमशील सोच से दूरी बढ़ी। कुछ समय पहले प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था 'प्रथम' की एनुअल स्टेटस आफ एजुकेशन रिपोर्ट में सामने आया था कि आठवीं पास करने वाले अधिकतर विद्यार्थी सामान्य गणित के प्रश्न हल करना भी नहीं जानते। इतना ही नहीं, 27 प्रतिशत विद्यार्थियों की ठीक से हिंदी पढ़ना-लिखना नहीं आता। इस रिपोर्ट के अनुसार देशभर में चार बच्चों में से एक बच्चा साधारण स पाठ पढ़ना सीखे बिना ही आठवीं कक्षा तक पहुंच जाता है। ऐसे में मूल्यांकन व्यवस्था को गंभीरता से लेने का सोच ही बच्चों को सीखने-समझने के मोर्चे पर सजग रख सकता है। शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार मानने वाले हमारे देश में बच्चों के लिए समान और सुलभ शिक्षा प्रणाली हो नहीं, परीक्षा का महत्व समझना भी आवश्यक है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

डिजिटल साम्राज्यवाद का प्रभाव

'नए रूप में साम्राज्यवादी शक्तियां' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में बलबीर पुंज ने साम्राज्यवाद के आधुनिक रूपों के माध्यम से सांस्कृतिक, आर्थिक और डिजिटल प्रभुत्व के खतरों का विश्लेषण करते हुए इसके प्रभावों और समाधान की ओर ध्यान आकर्षित किया है। आधुनिक युग में साम्राज्यवाद ने अपने पारंपरिक रूप से हटकर एक नया और जटिल स्वरूप ग्रहण कर लिया है। यह अब केवल सैन्य या राजनीतिक नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और डिजिटल क्षेत्र में भी अपने पैर पसार चुका है। यह नया साम्राज्यवाद सीधे नियंत्रण के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से देशों की नीतियों और समाजों को प्रभावित कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आज की सबसे बड़ी चुनौती बन गई हैं। ये कंपनियां विकासशील देशों के संसाधनों और श्रम का शोषण कर अपनी लाभप्रदता को बढ़ा रही हैं। इसके चलते स्थानीय उद्योग हाशिये पर चले जाते हैं और विदेशी निर्भरता बढ़ती जाती है। सांस्कृतिक क्षेत्र में विदेशी मीडिया और मनोरंजन उद्योग ने भारतीय समाज में उपभोक्तावाद को इस हद तक बढ़ावा दिया है कि परंपरागत मूल्य और सांस्कृतिक धरोहर कमजोर हो रही हैं। डिजिटल युग में डाटा का इस्तेमाल एक नए हथियार के रूप में किया जा रहा है। बड़ी तकनीकी कंपनियां व्यक्तिगत और सामाजिक डाटा का उपयोग करके न केवल व्यावसायिक लाभ कमा रही हैं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक नियंत्रण भी स्थापित कर रही हैं। इस समस्या से निपटने के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना होगा। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक मूल्यों और भारतीय इतिहास को मजबूत आधार बनाया जा सकता है। इसके साथ ही डिजिटल तकनीक में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना और स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहित करना साम्राज्यवाद के इस नए स्वरूप को चुनौती देने का कारगर तरीका हो सकता है।

awanishg30@gmail.com

व्यसनों को छोड़ना भी पुरुषार्थ

जो पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषार्थ ही काम आता है। फिर वह पुरुषार्थ चाहे अर्थ का हो या धर्म का। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ होता है। वर्तमान में व्यसन से बचने वाला भी पुरुषार्थी होता है। पग-पग पर आज व्यसनों का बाजार लगा है। इस बाजार से हम दूर रहें, यह हमारे पुरुषार्थ से ही संभव है। व्यसनों से बचकर चलने वालों के साथ समृद्धि चलती है। जो व्यसन के जाल में फंस गया, वह दरिद्रता को आमंत्रण देता है। शराब, जुआ, नशीली वस्तुओं और रसायन युक्त ड्रग्स का सेवन कर युवा जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। नशा नाश करता है। सज्जन व्यक्ति व्यसन ग्रस्त लोगों से व्यसन त्यागने हेतु प्रेरित करके उसका कल्याण चाहते हैं। आज सरकार भी चाहती है कि समाज व्यसनों से मुक्त बने। प्रतिदिन व्यसन मुक्ति दिवस मनाए जाते हैं, सभाएं होती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, फिर भी हमारा समाज इस कीचड़ से निकल नहीं पा रहा है। यह सब देखकर लगता है, हमारे प्रयासों में कमी है। जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उनमें पुरुषार्थ का अभाव है। नशा करने वालों से नशा मुक्ति आंदोलन का उद्घाटन कराया जाता है तो यही हश्र होगा। देश में दरिद्रता बढ़ती जाएगी। एक व्यसन से दूसरे व्यसन की बल मिलता है। व्यसन बुद्धि को भ्रमित कर देता है और मृत्यु के द्वार पर ले जाता है। व्यसनों से चरित्र का नाश होता है। जो पुरुषार्थ को त्याग देता है, वही मृत्यु के पथ का अनुगामी बन जाता है। देश में शराब पीने की लत से हर वर्ष लाखों लोग मरते हैं। नशे में गाड़ी चलाने से मरने वाले की संख्या में युवा सबसे ज्यादा है। प्रतिवर्ष 7,334 मौत में शराब का योगदान होता है। हत्या के 48 प्रतिशत दोषी हत्या करते समय नशे में होते हैं। अत्यधिक शराब के कारण होने यकृत रोग होने पर भी लोग बड़ी संख्या में मरते हैं। शराब सहित हर नशा जहर है। इससे बचकर रहना है।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
आपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

6 प्रशिक्षित हाई स्कूल के शिक्षकों ने सीखा महामारी आर्मोरेशन में कि कक्षा में पढ़ाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का कोई मतलब है, एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, जबकि 94 प्रशिक्षित शिक्षकों ने क्लासरूम में एआइ के उपयोग फिर जाने का प्रयोग किया है।

आजकल

शिक्षा व्यवस्था में एआइ का उपयोग

हालही में केरल के एक शिक्षण संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में जोड़ा है। पंजाब, मध्य प्रदेश और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में या तो विषय के तौर पर एआइ को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है या ऐसा करने की योजना है। कई निजी विश्वविद्यालयों में एआइ को एक अलग डिग्री कोर्स के रूप में भी शामिल किया जा रहा है। ऐसे में इससे संबंधित कई प्रकार की आशंकाएं भी सामने आ रही हैं, जिनपर विचार किया जाना चाहिए

डा. संजय वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, वेनेट यूनिवर्सिटी, सेंटर वेण्डा

लगभग दो साल पहले नवंबर 2022 में ओपनएआइ नामक कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) संचालित पहला भाषाई चैटबाट- चैटजीपीटी लांच किया था, तो सनसनी फैलाने वाले इस आविष्कार को लेकर सबसे तीखी प्रतिक्रियाएं शिक्षा जगत से ही मिली थीं। पदार्पण के पांच दिनों के अंदर दुनिया भर में चैटजीपीटी के दस लाख लोगों के ग्राहक बनने के बावजूद शुरुआती दिनों में ही अमेरिका में कुछ विश्वविद्यालयों में इसके उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई थी। न्यूयार्क और सिएटल स्थित विश्वविद्यालयों-कालेजों के प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि उनके छात्र कैंपस में मौजूद रहने के दौरान अपने स्मार्टफोन और लैपटाप तथा सर्वर से जुड़े कंप्यूटरों पर चैटजीपीटी नहीं खोल पाएं।

अभी इस चर्चा का महत्व यह है कि हाल में केरल के एक शिक्षण संस्थान ने कई विषयों की पढ़ाई के लिए एआइ को बतौर विषय पाठ्यक्रम में जोड़ा है। देश के कई निजी विश्वविद्यालयों में एआइ को न केवल एक अलग डिग्री कोर्स की तरह लिया जा रहा है। यह तब है, जब शिक्षाशास्त्री और विशेषज्ञ इस जल्दबाजी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये शिकायत कर रहे हैं कि एआइ की मदद छात्रों की मौलिकता पर ग्रहण लगा रही है। ऐसी स्थिति में यह सवाल एक गंभीर विवेचना का विषय बन गया है कि इस दूसरे तमाम क्षेत्रों में एआइ की उल्लेखनीय भूमिका सामने आने के बावजूद क्या शिक्षा जगत को इससे अलग रखना चाहिए या फिर नए किस्म के ज्ञान की बढ़ती गंगा में हाथ धोने से चूकना नहीं चाहिए।

दवाओं जैसा क्लिनिकल ट्रायल : विज्ञान और चिकित्सा जगत में एक नियम बहुत प्रचलित है कि कोई भी नई ईजाद आम जनता के सामने तब तक नहीं लाई जानी चाहिए, जब तक उसके दुष्प्रभावों का सटीक आकलन नहीं हो जाए। चिकित्सा से जुड़े फार्मा उद्योग के लिए तो इसके लिए कड़े मानक हैं कि किसी दवा या टीके को बनाने के बाद लंबे समय तक उसका मानवीय चिकित्सा परीक्षण होना चाहिए। कोविड महामारी की जटिल और आपदाकारी स्थितियों को छोड़ दें तो ऐसे अवसर कम ही आए हैं, जब किसी दवा या टीके को लंबे परीक्षण के बिना आम जनता को उपलब्ध कराया गया हो। दुनिया के तकनीकी और औद्योगिक विकास के क्रम में भी कोई मशीन या आविष्कार वर्षों या कई बार तो दशकों के प्रयोगों-परीक्षण के बाद इस स्थिति में आया है कि आम लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। यहां तक कि कंप्यूटर जैसी मशीन और इंटरनेट जैसे तकनीक को अपनाने में भी दुनिया को कई दशक लग गए। लेकिन एआइ को अपनाने के संबंध में भारत समेत दुनिया के कई देशों में एक किस्म का उतावलापन दिखाई दे रहा है। इंटरनेट और तकनीक से जुड़ी निजी कंपनियों को इसमें अपना मुनाफा नजर आ रहा है, लेकिन सरकारों पर भी इसका पर्याप्त दबाव दिखाई दे रहा है कि वे अपने कार्यलयों में एआइ से जुड़े प्रबंधों को जितना जल्दी हो सके, लागू कर दें। इसमें संदेह नहीं है कि उद्योग जगत और इंटरनेट से संचालित अर्थव्यवस्था में इस चमत्कारी तकनीक (एआइ) के बेशुमार फायदे हैं। इस नजरिए से वहां एआइ टूल्स और सफ्टवेयर अपनाना समझदारी हो सकता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एआइ को लेकर तेजी से बन रही स्वीकारोक्ति किसी दबाव का नतीजा ज्यादा लगती है, बजाय इसकी जरूरत के। ऐसा क्यों है, इसे कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है।

आनलाइन पढ़ाई और एआइ : इतिहास में ज्यादा पीछे जाए बगैर हाल के पांच वर्षों में तकनीकी करिश्मे की बदौलत संभव हुई पढ़ाई के एक प्रमुख उदाहरण- आनलाइन शिक्षा को देखें, तो पता चलता है कि इससे कितनी बड़ी समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। कोविड महामारी के दौरान हर किस्म की शिक्षा को जारी रखने का इकलौता विकल्प बरास्ता इंटरनेट कंप्यूटर, लैपटाप या स्मार्टफोन के जरिए पढ़ाई करना था। मजबूरी में अपनाए गए इस विकल्प के नतीजे में जो पीढ़ी अगली कक्षाओं में गई, उसके लिए ''कोविड पीढ़ी'' जैसे जुमले गढ़े गए। इस पीढ़ी ने स्मार्टफोन के आगे सोते हुए या कोई खेल करते हुए पढ़ाई कर अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट लिए हैं और इसका ज्ञान शून्य है। इसमें अमीरी-गरीबी का फर्क भी दिखा। जो लोग संसाधनविहीन थे, उनके लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन जुटाना आर्थिक समस्याओं की वजह बन गया। इससे असमानता बढ़ी और पढ़ाई के नतीजे खराब हुए। इधर, कुछ वैसी ही जल्दबाजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में एआइ को लेकर दिखाई दे रही है।

पूछा जा सकता है कि शिक्षा बोर्डों, विश्वविद्यालयों और स्वयं सरकारों के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि वे छात्रों को एआइ की जानकारी से लैस करना चाहते हैं। दावा है कि इसके पीछे असल में एआइ और डाटा एल्गोरिम से जुड़ी तकनीकी व इंटरनेट कंपनियों का दिमाग है। ये कंपनियां अपने कारोबारी उद्देश्य के लिए एआइ से जुड़ा डाटा पैदा करके उसका इस्तेमाल करना चाहती हैं, ताकि एल्गोरिम को उनकी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन कर सकें। इस बारे में यूनेस्को के एक विरोधाभ का तर्क है कि इन कंपनियों का ध्यान शिक्षा से अधिक लाभ पर है। ऐसे में यह देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा एक ऐसा जरिया बन गया है, जहां एआइ के इस्तेमाल से भविष्य के उपभोक्ताओं तक आसान पहुंच बनाई जा सकती है। इसके लिए ये कंपनियां सरकारों और शिक्षा जगत को एआइ के लिए लुभा रही हैं और इसके लिए बेहद सस्ती दरों पर एआइ के एप्लिकेशन और संबंधित तकनीकें बेचकर उन्हें अपने झांसे में ले रहे हैं। पर क्या शिक्षा जगत में एआइ के कुछ लाभ भी हैं।

भ्रम का शिकार : अब सवाल है कि एक आइटी राष्ट्र के तौर पर दुनिया में काफी दबदबा रखने वाले हमारे देश के शिक्षा जगत में एआइ को लेकर क्या रुख अपनाया जाना चाहिए। इस सवाल के जवाब में विकसित देशों के उदाहरण देना समीचीन होगा। एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में महज छह प्रतिशत हाई स्कूल शिक्षकों ने माना है कि कक्षाओं में पढ़ाई के लिए एआइ के इस्तेमाल का कोई मतलब है। यानी 94 प्रतिशत शिक्षक इसके विरोध में हैं। वहीं फ्रांस में इसी तरह की एक पहल के रूप में जब गृहकार्य करने के लिए होमवर्क एप ''एमआइए'' लाने की घोषणा हुई, तो इसके समर्थन-विरोध में वहां राजनीतिक संकट की स्थिति बन गई। अंततः इस योजना को रद्द कर दिया गया। ब्रिटेन में भी इसी तरह का एक एआइ एप ''स्पार्क्स'' लाया गया, तो तमाम अभिभावकों ने इसे लेकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इससे पढ़ाई का मजा जाता रहा है और बच्चे इससे कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह बताई गई है कि ये ज्यादातर एआइ टूल या एप बच्चों को उस समाज से काट देते हैं, जहां वे परस्पर संवाद से बहुत कुछ मौलिकता के साथ सीखते हैं। एआइ की दुनिया बेशक तेज हो, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी हकीकत यह है कि यह सच्चाई से अलग एक ऐसी दुनिया में ले जाती है, जहां नकली चीजें असली लगती हैं और पराए ज्ञान को लोग अपना मानकर किसी भ्रम के शिकार हो सकते हैं।

सीमाओं को समझते हुए ली जाए एआइ की मदद

बर्तमान सदी के पदार्पण के साथ दुनिया में यह बहस जोरों पर थी कि यदि कंप्यूटर इसी तरह हावी हो गए, तो वे भारी तबाही ला सकते हैं। नौकरियां जा सकती हैं, कंप्यूटर वायरसों के हमले से दुनिया का बेड़ा गर्क हो सकता है। कंप्यूटरीकृत नेटवर्क और इंटरनेट प्रणालियों के गाहे-बगाहे गच्चा देने संबंधी बाकये हालांकि इस नई सदी का चौथाई हिस्सा बीतने पर भी जारी हैं, परंतु कमोबेश कंप्यूटर और इंटरनेट ने दुनिया को बेहतर ही बनाया है।

नौकरियां जाने के बजाय उनमें कई गुना बढ़ोतरी ही हुई है। इसलिए एआइ को लेकर पैदा चिंताओं का यह मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि इस नई तकनीक से पूरी तरह किनारा करने में ही मानवता की भलाई है। बल्कि आवश्यकता यह है कि इसका इस्तेमाल किस क्षेत्र में हो, कितना हो, यह सीखा जाए। जैसे अगर खराब गुणवत्ता वाली फोटो को अच्छी गुणवत्ता में बदलना है, तो एआइ टूल की मदद अपरिहार्य है। दवाओं और वैक्सीनों के तेज विकास की जरूरत है, तो एआइ से लैस सुपर कंप्यूटरों की मदद लेना इंसानियत की भलाई करना ही है। चेहरों की डिजाइनिंग, स्केच बनाने, इमेज और कार्टून बनाने में अगर एआइ टूल अपनी सिद्धहस्तता दिखाते हैं, तो उनसे परहेज करना समझदारी नहीं है। यहां तक शोध पत्र लिखने में भी अगर कोहिंग को समझने की जरूरत है, शुरुआती गहन (पहला पैराग्राफ) या फिर सारांश लिखने में समस्या है, तो वहां एआइ की मदद ली जा सकती है।

शोध कार्य में भी इसका महत्व है कि शोधार्थी ने किसी विषय का आकलन कैसे किया है और चीजों को नए संदर्भों में कैसे प्रस्तुत किया है। अगर उसने कक्षा में प्रोफेसर की कही बातों को एक तोते की तरह रटकर प्रस्तुत किया है, तो यह उसकी गलती है। समझना होगा कि एआइ टूल्स अपने लिखे लेखों-निबंधों को भी नहीं समझते हैं। उन्हें उनमें प्रस्तुत भाषाओं-शब्दों के वास्तविक अर्थ नहीं मालूम हैं। वे तो महज उन तथ्यों और भाषाओं को उस व्यवस्थित क्रम में ही प्रस्तुत करते हैं, जिनका डाटा उन्हें उपलब्ध कराया गया है। उनसे मिली सामग्री की भाषा एक विशेषज्ञ द्वारा लिखी सामग्री जैसी हो सकती है, लेकिन वह तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकती है। उनका संपादन अकादमिक स्तर का नहीं होगा। उनमें समीक्षा (रिव्यू) और संपादन की ऐसी त्रुटियां होंगी, जो प्रायः इंसान नहीं करते हैं। चूंकि एआइ से तैयार सामग्री में तथ्यों को महज प्रोसेस करके प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए वह सामग्री न तो ज्ञान में वृद्धि करेगी और न ही मौलिकता हासिल करने का अवसर देगी। इन दायरों को समझकर यदि एआइ की मदद ली जाती है, वह कुछ अर्थों में सार्थक कही जा सकती है।

(डा. संजय वर्मा)

खरी-खरी

आओ विकास करें

पूरन सरमा

हमारे देश को विकास की बीमारी आजादी के बाद ही लग गई थी। जो भी सत्ता में आया उसने विकास का नारा दिया। आप विकास चाहें या न चाहें, परंतु सरकार ने कहा कि विकास तो कराना ही होगा। विकास नहीं होगा तो सरकार के कार्यक्रम और योजनाओं का क्या होगा? वे विकास की मारामारी ऐसी चली कि विकास चल निकला। हम विकासशील हो गए।

यही विकास एक दिन मेरे गांव भी आ गया। कुछ सिरफिरों को पसंद भी आ गया। उन्हें लगा कि विकास की यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, इसलिए वे भी विकासशील हो गए। इसे अपनाने वाले वे लोग थे जो बेकार थे, जिनके हाथ खाली थे। उन्होंने विकास को आजीविका के रूप में अपना लिया। वह विकास ही किस काम का जिसे अपनाने से सर्वप्रथम स्वयं का कल्याण न हो। बस दनादन पुख्ता मकानों की नींव धरी जाने लगी। इस तरह वे आबाद हो गए। गांव के विकास के लिए 'नवयुवक मंडल' नाम से एक संस्था का गठन किया गया।

मंडल की पहली बैठक हुई तो उसके एजेंडा में मेरा नाम स्थानांतरित कराए जाने वाले लोगों में शामिल था। मैं घबरा गया कि इस नवयुवक मंडल का गठन क्या मेरे लिए ही किया गया है। दौड़ कर मैं विकासशीलों के अध्यक्ष से मिला और बोला, 'अर्मा यार, तुम हमारे गांव के हो और हमारा ही तबादला करवा रहे हो। गांव में पढ़े हैं। अपने बच्चें का लालन-पालन कर रहे हैं, यदि तबादला हो गया तो सारा घर अव्यवस्थित हो जाएगा।'

अध्यक्ष जी तो विकास की लहर के शिकार थे सो बोले, 'गांव के विकास के लिए आपका इस गांव से स्थानांतरण अत्यावश्यक है। मंडल की बैठक में भी यह प्रस्ताव पारित हो गया है, इसलिए अब कुछ नहीं किया जा सकता।'

'लेकिन मैं विकास में आड़े कहां आ रहा हूं और मैंने बिगड़ा क्या है?' मैंने पूछा।

वे बोले, 'विकास में आप ही सबसे बड़ी बाधा हो। दरअसल आपने झंझानदरी का प्रमाण-पत्र ले रखा है और हमें झंझानदरी से डर लगता है। स्कूल में जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसका सारा हिसाब-किताब आपके पास है।'

पोस्ट

व्यवसाय केवल काम नहीं है, बल्कि यह अपने जुनून को विरासत में बदलने का जरिया है। हर्ष गोयनका@hvgoenka

18 से 50 की उम्र खटने की होती है, लेकिन इस आयु वर्ग में मुफ्तखोरी की आदत डाल देश भर की सरकारें मानव संसाधन को अपने ऊपर बोझ बना रही है। यह आबादी देश को ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी निभाती, लेकिन घर बैठे पैसे मिलेंगे तो लोग काम क्यों करेंगे।
अखिलेश सिंह@akhileshsi1

अनावश्यक आक्रामकता से बचना और मैदान पर शांत व्यवहार, यही वह चीज है जो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बनाती है। मि. सिन्हा@MrSinha_

आस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के मुख्य खिलाड़ी ट्रेविस हेड के आउट होने पर जसप्रीत बुमराह ने कैसे जश्न मनाया? कोई अतिशयोक्तिपूर्ण व्यवहार नहीं, कोई उछलकूद या आक्रामकता नहीं, बस एक मुस्कान। नई पीढ़ी इससे सीखे और अपने आदर्श को समझदारी से चुने।
मोहम्मद कैफ@MohammadKaif

शशिशेखर
संपादकीय प्रभारी, रांची

झारखंड डायरी

पेसा कानून की प्रतीक्षा में प्रदेश

जनजाति बहुल अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देने वाले 'पेसा' कानून के लागू होने का इंतजार झारखंड समेत कई राज्य कर रहे हैं। जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों को विशेष अधिकार दिलाने वाला यह कानून झारखंड के चुनावों में मुद्दा भी बनता रहा है और सभी दल इसे लागू कराने की बात करते हैं, लेकिन पेसा को लेकर आज तक राज्य में नियमावली नहीं बन सकी है। अच्छी बात यह है कि केंद्र और राज्य दोनों ने हाल के दिनों में इस कानून के प्रति गंभीरता दिखाई है।

हाल ही में पेसा कानून को लेकर रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव बिनोद भारद्वाज ने कहा कि केंद्र जनजातीय समुदाय की परंपरा और संस्कृति का दस्तावेजीकरण करेगा। गांव-गांव की सांस्कृतिक धरोहरों को भी संरक्षित किया जाएगा। आगामी 26 जनवरी से इसकी शुरुआत झारखंड से होगी और 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ से। उधर, झारखंड सरकार पेसा एक्ट के तहत नियमावली बनाने के लिए अभी रायशुमारी कर रही है। इन प्रयासों ने लोगों के मन में उम्मीद बढ़ाई है।

इसी साल जुलाई में हाई कोर्ट ने भी पेसा एक्ट को लेकर सरकार के उदासीन रवैये पर नाराजगी जाहिर की। राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह दो महीने में इसकी नियमावली बनाए। वहीं, राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी इस कानून को लागू करने का आग्रह किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि सरकार राज्यवासियों की भावना के अनुरूप कार्य कर रही है। पेसा पर पहले से चर्चा हो रही है। इस विषय पर जल्द ही फैसला सरकार लेगी। केंद्र सरकार ने 24 दिसंबर 1986 को पेसा कानून लागू किया था। देश में कुल दस 'पेसा' राज्य हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में शामिल हैं।

प्रदेश के आदिवासी समूहों में पेसा कानून को लेकर उत्सुकता कायम है। फाइल

कुछ राज्यों में यह आंशिक रूप से लागू हुआ है, लेकिन ओडिशा व झारखंड में यह कानून लागू नहीं हो सका है।

पेसा कानून का पूरा नाम है- पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। वर्ष 1986 में पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार करते हुए पेसा कानून की शुरुआत हुई। इस कानून की तीन प्रमुख बातें हैं- जल, जंगल और जमीन का अधिकार। जंगल और गांव की जमीन पर ग्रामीणों को अधिकार देते हुए यह कानून आदिवासियों को सशक्त बनाता है। जिन अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा होगी, वहां संबंधित विभाग को उस क्षेत्र में जल संग्रह करने की व्यवस्था, मिट्टी के कटाव रोकने आदि के काम करने होंगे। ग्रामीणों को ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं के लाभ दिलाने और जमीन संबंधी कागजात उपलब्ध कराने आदि की भी व्यवस्था है, ताकि ग्रामीणों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ें। इस कानून के दायरे में आने वाले लोगों को उसी क्षेत्र में जमीन से जुड़ी सुविधाएं दी जाएंगे। गांवों की जमीन से जुड़े जो भी मामले होंगे उसका ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करेगी और मुखिया को भेजेगी। मुखिया इसमें सुधार करेंगे। आदिवासियों की जमीन अगर किसी गैर-आदिवासी के पास चली जाती है तो उन्हें वापस पाने का भी अधिकार है। इस तरह पेसा कानून के जरिये आदिवासियों के पास जमीन को लेकर अधिकार बढ़ेंगे। झारखंड जैसे राज्य में बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित हुई है। वहीं गांवों की बड़ी आबादी का जीवन जंगलों पर निर्भर है। ऐसे में यहां इस कानून की अहमियत और भी बढ़ जाती है।

पेसा कानून के तहत यह व्यवस्था है कि अगर किसी क्षेत्र में किसी की जमीन नीलाम हो रही है तो वह जमीन आदिवासी को ही दिलाई जाएगी। इतना ही नहीं, बंटाई के लिए किसी जमीन को बंधक रखा गया है तो उसे आदिवासियों को देने के अधिकार ग्राम सभा को दिए जाए जाएंगे। वहीं, ग्राम सभा के पास जल प्रबंधन के अधिकार रहेंगे। अगर किसी प्रोजेक्ट या हाइवे जैसे निर्माण के लिए आदिवासियों की जमीन ली जाती है तो उसमें ग्राम सभा की अनुमति सबसे ज्यादा मायने रखेगी। इसके लिए डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी उस क्षेत्र की ग्राम सभाओं से पहले चर्चा करेंगे। उनकी अनुशंसा के बाद जमीन ली जाएगी। ऐसे मामलों में आदिवासियों से छल-कपट न किया जा सके, पेसा एक्ट में इस बात का ध्यान रखा गया है।

पेसा को लेकर कुछ वैचारिक अंतर्विरोध भी है। झारखंड आदिवासी सरना किसान समिति, जनजाति सुरक्षा मंच आदि संगठनों ने सरकार की नियमावली पर शंका जाहिर की है। समिति ने कहा है कि पेसा नियमावली कुछ इस तरह की बनी है कि कुछ खास समूह को ही इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार को यह भी देखना है कि केंद्र की जो मंशा है, उसी अनुरूप नियमावली बने और जल्द से जल्द लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो। झारखंड का निर्माण आदिवासी हितों के लिए किया गया और उनके हित के कानून ढाई दशक तक लटके रहेंगे तो कैसा हित सधेगा?

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या अजय कुमार मल्ला को राज्यपाल बनाए जाने से मणिपुर समस्या का समाधान निकलने की उम्मीद बढ़ गई है?

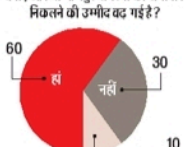

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का रुख आइएनडीआइए के टूटने का संकेत है?

परिणाम जागरण डाटा स्टेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

दिल्ली में तो खिंच गई 'इंडी' में तलवार, एक-दूसरे पर करें 'आप'-कांग्रेस वार। 'आप'-कांग्रेस वार क्रोध में दिखते माकन, चाह रही हैं 'आप' कांग्रेस का निष्कासन। सच है जब कांग्रेस बनी थी भीगी बिल्ली, तभी केजरीवाल आए कब्जाए दिल्ली!
- ओमप्रकाश तिवारी

हरियाणा डायरी

हार के बाद कांग्रेस में तकरार

अनुराग अग्रवाल
राज्य ब्यूरो प्रमुख, हरियाणा

हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस पटरी से उतरी हुई है। कांग्रेस हाईकमान ने जहां विधायक दल के नेता का चयन अटका रखा है, वहीं पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के बीच हार को लेकर जबरदस्त आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं। प्रदेश में अगले माह शहरी निकाय चुनाव होने हैं। कांग्रेस निकाय चुनाव के माध्यम से प्रदेश की राजनीतिक मुख्यधारा में लौटने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने सभी 22 जिलों के प्रभारी नियुक्त किए थे, लेकिन प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने यह कहते हुए प्रदेश अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची को रद्द कर दिया कि उनसे इस बारे में सलाह नहीं की गई। प्रदेश में पिछले 10 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है।

लोकसभा और विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने बिना संगठन के ही लड़े थे। प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि पार्टी प्रभारी ने उनके द्वारा भेजी गई प्रदेश पदाधिकारियों की सूची को कभी हाईकमान के पास पहुंचाया ही नहीं, जबकि पार्टी प्रभारी का दावा है कि यह सूची एकतरफा थी, जिसमें सैलजा और सुरजेवाला के समर्थकों की अनदेखी की गई थी। प्रदेश अध्यक्ष को कई बार ऐसी सूची तैयार करने को कहा गया, जिसमें सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व हो, परंतु वे इसे करने में सफल नहीं हो पाए। फूलचंद मुलाना, डा. अशोक तंवर और कुमारी सैलजा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा नहीं हो पाई थी। तब भी विवाद उठा था कि लिस्ट में हुड्डा गुट की अनदेखी की जा रही है, जिसे हाईकमान ने मंजूरी नहीं दी।

दीपक बाबरिया। फाइल

चौधरी उदयभान। फाइल

अब ताजा विवाद जिला प्रभारियों की नियुक्तियों को लेकर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने छह विधायकों और 14 पूर्व विधायकों व पूर्व मंत्रियों को जिला प्रभारी नियुक्त किया था। 18 दिसंबर को घोषित इस सूची पर पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया ने 24 दिसंबर को एक अधिकृत पत्र जारी करते हुए रोक लगाई है। उनका मानना है कि प्रदेश प्रभारी और हाईकमान की मंजूरी के बिना कोई जिला प्रभारी नियुक्त नहीं किया जा सकता। इस सूची पर सबसे ज्यादा आपत्ति कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को है, जिसमें उनके समर्थकों के नाम शामिल नहीं थे।

दीपक बाबरिया और सैलजा व सुरजेवाला के राजनीतिक रिश्ते पूर्व में अच्छे नहीं रहे, लेकिन जब जिला प्रभारियों की सूची पर सैलजा व सुरजेवाला की आपत्ति आई तो बाबरिया ने उसे रद करने देरी नहीं लगाई। दरअसल, कांग्रेस प्रभारी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बीच विवाद तब आरंभ हुआ, जब उदयभान कुछ जिलों में अपनी निजी पसंद के नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिलाना चाहते थे, मगर दीपक बाबरिया ने उनकी निजी पसंद को महत्व नहीं दिया। इसके बाद लोकसभा चुनाव में बाबरिया पर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने के दबाव बनाए गए, जिनके चुनाव लड़ने की स्थिति में कांग्रेस की हार पहले से तय मानी जा रही थी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी टिकटों के आबंटन में ऐसा ही हुआ। चुनाव नतीजे आने के बाद बाबरिया व उदयभान के बीच तनातनी बढ़ गई। उदयभान ने मीडिया के समक्ष कहा कि करीब एक दर्जन विधानसभा सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी की सूचना मतदान वाले दिन पार्टी प्रभारी के पास थी, लेकिन उन्होंने इस सूचना को आगे किसी वरिष्ठ नेता के पास नहीं पहुंचाया।

कुछ दिन तो बाबरिया इस आरोप पर चुप रहे, लेकिन मामला जब तूल पकड़ गया तो उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया कि उनके पास जो भी सूचना आई थी, उसे तुरंत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंचा दिया गया था, जिसके बाद उदयभान ढीले पड़ गए और उन्हें यह कहकर सफाई देनी पड़ी कि उनके पास किसी दूसरे फोन नंबर से आधी अधूरी सूचना आई थी। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अलग से यह सिद्ध करने में लगी है कि विधानसभा चुनाव में ईवीएम में ही खेल हुआ है और कांग्रेस की हार का कारण प्रशासन द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी करना रहा है।

फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अनुसार बैलेट वोटों की गिनती के समय कांग्रेस 70 सीटों पर आगे थी, जबकि ईवीएम खुलने के बाद यह आंकड़ा गिरता चला गया। चुनाव आयोग ने पांच अक्टूबर को शाम पांच बजे 61.19 प्रतिशत वोटिंग दिखाई थी। उसी रात पौने 12 बजे बजे साइट पर 65.65 प्रतिशत वोटिंग दिखाई गई। मतगणना के एक दिन पहले रात पौने नौ बजे साइट पर वोट प्रतिशत को बढ़ाकर 67.90 प्रतिशत कर दिया गया। वोटिंग से लेकर मतगणन तक प्रत्येक विधानसभा में 15 हजार 175 वोट बढ़ने का अनुमान है। प्रदेश की शहरी सीटों वाली मशीनों के साथ अधिक छेड़छाड़ की गई है। कुल मिलाकर कांग्रेस नेताओं की स्थिति इस समय आपस में लड़ने से ज्यादा कुछ नहीं है। हुड्डा समर्थक सांसद अलग चल रहे हैं और कुमारी सैलजा एवं रणदीप सुरजेवाला की अपनी अलग राजनीतिक व्यस्तताएं हैं, जिनसे पार्टी कार्यकर्ता स्वयं को अकेला महसूस कर रहे हैं।

****

सम्पादकीय

निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार कूटनीति पर जोर

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय एक बैठक आयोजित करने जा रहा है। उसमें इस पर विचार किया जाएगा कि कैसे छह खास उत्पाद क्षेत्रों में निर्यात मूल्य बढ़ाया जा सकता है। इसमें खास तौर पर पश्चिमी देशों के अलावा रूस, चीन और इंडोनेशिया समेत 20 प्रमुख बाजारों को ध्यान में रखा जाएगा। नीति निर्माता और प्रशासक देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा लगा रहे हैं और जिस रुचि का प्रदर्शन कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है। यह भी अच्छी खबर है कि राजदूतों समेत देश के राजनयिकों को इस रणनीति पर चर्चा के लिए प्राय: आमंत्रित किया गया है। हालांकि देश के राजनयिकों के समूह के सबसे वरिष्ठ लोगों का मानना है कि व्यापार संवर्धन का काम उनके कामों के अन्य पहलुओं के बाद आना चाहिए। ऐसा माना जा सकता है कि इस प्रयास की वजह देश के वाणिज्यिक निर्यात में हाल के समय में आई गिरावट है। पिछले महीने यह दो वर्षों के अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। ऐसे में एक लक्षित निर्यात नीति को जरूरी माना जा रहा है। यह बात पहले ही स्पष्ट है कि देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या करने की आवश्यकता है? सरकार को सुधार के इसी एजेंडे पर आगे बढ़ना है और आधुनिक व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखकर चलना है। उदाहरण के लिए जिन 20 देशों की सूची बनाई गई है उनमें से कई यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। उस क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने का स्वाभाविक तरीका यह है कि एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएं। इस पर लंबे समय से बातचीत जारी है। बिना व्यापार संतुलन के निर्यात बढ़ाने का विचार पुराना हो चुका है।

अगर निर्यात बढ़ाना है तो संभावित विदेशी साझेदारों को भारतीय बाजार में पहुंचने देना होगा। अन्य क्षेत्रों में मसलन अमेरिका आदि के साथ मुक्त व्यापार समझौता होता नहीं दिखता। खास तौर पर डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल को देखते हुए यह मुश्किल लगता है। ऐसे में इन क्षेत्रों को निर्यात बढ़ाने का सवाल किफायत, प्रतिस्पर्धी क्षमता और लागत में कमी पर निर्भर करता है। प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होना होगा। उसके लिए स्थिर व्यापार और कर नीति की आवश्यकता है। देश में करों और टैरिफ को लेकर परिवर्तनशीलता और आयात की गुणवत्ता तय करने के लिए मनमाने गुणवत्ता मानक आदेशों ने भी वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के प्रवेश को बाधित किया है। ऐसे में अमेरिका जैसे बाजारों में निर्यात बढ़ाने की उसकी क्षमता भी प्रभावित हुई है। यकीनन कारोबारी मित्रता के लिए प्रशासनिक से लेकर न्यायिक सुधारों तक जमीनी सुधार भी जरूरी हैं। परंतु खास तौर पर व्यापार के लिए नए समझौतों पर तथा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पर सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। बुनियादी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, किसी नई रणनीति की नहीं। ऐसे में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि जब भी बैठक हो, उसमें सरकार के पास यह फीडबैक भी जाना चाहिए। व्यापार नीति सुधार लंबे समय से लंबित हैं। इस दिशा में हाल के दिनों में जो काम किया गया है वह लक्ष्य तय करने अथवा खास कंपनियों मसलन ऐपल आदि को लुभाने का रहा है।

मिर्जा गालिब जयन्ती पर विशेष

मिर्जा गालिब : शायरी और गजल के शिखर फनकार थे

गालिब की प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में स्पष्टतः कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने अधिकतर फारसी और उर्दू में पारम्परिक मानवीयता, भक्ति और सौन्दर्य रस पर रचनायें लिखी। उन्होंने फारसी और उर्दू दोनो में पारंपरिक गीत काव्य की रहस्यमय-रोमांटिक शैली में सबसे व्यापक रूप से लिखा और यह गजल के रूप में जाना जाता है। उनकी शायरियों में गहन साहित्य और क्लिष्ट भाषा का समावेश था। उन्होंने अपनी शायरी का बड़ा हिस्सा असद के नाम से लिखा है।

ललित गर्ग

मिर्जा असदुल्लाह बेग खान,जो अपने तखल्लुस गालिब से जाने जाते हैं, उर्दू एवं फ़ारसी भाषा के एक महान शायर थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक एवं सार्वदैशिक महान शायर माना जाता है और फ़ारसी कविता के प्रवाह को हिन्दुस्तानी जबान में लोकप्रिय बनाने वाले व एक महान् फनकार थे। हर मोहब्बत करने वाला आशिक मिर्जा गालिब के शेर, शायरी और गजल जरूर पढ़ता है। कई उनकी शायरी का कायल है। मिर्जा गालिब सर्व-धर्म-सद्भाव एवं मानवीय चेतना के चितेरे थे एवं गहन संवेदनाओं के शिखर सृजनकार थे। गालिब का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक एवं बहुआयामी था। गालिब में जिस प्रकार शारीरिक सौंदर्य था, उसी प्रकार उनकी प्रकृति में विनोदप्रियता तथा वक्रता भी थी और ये सब विशेषताएं उनकी कविता एवं शायरी में यत्र-तत्र झलकती रहती हैं। चिन्ताओं से संघर्ष में इनकी सहायक एक तो थी शराब, जिन्दगी के अंतिम समय में जुए की लत भी लग गई। उन्हें शुरू से शतरंज और चौसर खेलने की आदत थी। अक्सर मित्र-मण्डली जमा होती और खेल-तमाशों में वक्त कटता था। अपने मदिरा प्रेम के कारण जो भाव प्रकट किए हैं, वे शेर ऐसे चुटीले तथा विनोदपूर्ण हैं कि उनका जोड़ उर्दू कविता में अन्यत्र नहीं मिलता। गालिब ने शायरी और गजल को एक नया रूप दिया। गालिब के पहले गजल को केवल प्रेम के संदर्भ में देखा जाता है लेकिन उन्होंने गजल में ही जीवन के दर्शन और रहस्यों को दर्शाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी शायरी के कारण वे न सिर्फ हिन्दुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आज भी उनका नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। गालिब हिंदुस्तान में उर्दू अदबी के दुनिया के सबसे रोचक किरदार थे। उनकी जड़ें तुर्क से थीं। वे फारसी कविता को भारतीय भाषा में लोकप्रिय करने में माहिर थे, उन्हें पत्र लिखने का बहुत शौक था। इसीलिए उन्हें पत्र-पुरोधा भी कहा जाता था। आज भी उनके पत्रों को उर्दू साहित्य में एक अहम विरासत माना जाता है। मिर्जा गालिब ने 11 वर्ष की छोटी उम्र में ही अपनी पहली कविता लिखी थी। मिर्जा गालिब की मातृभाषा उर्दू थी लेकिन तुर्की और फारसी भाषाओं पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। उन्होंने अरबी, फारसी, दर्शन और तर्कशास्त्र का भी अध्ययन किया था। गालिब इश्क को जीते थे। वह इश्क का आखिरी छोर थे। उनकी नज्में और शेर ने सालों साल इश्क की तहजीब दुनिया को दी है। अगर हम यूं कहें कि इश्क गालिब से शुरू होता है तो यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। उनका हर शेर एक जिंदादिल आशिक की तरह इश्क की रस्मों को निभाता है। उनका जीवन संघर्ष से भागते या पलायन करते हुए नहीं बिता और न इनकी कविता एवं शायरी में कहीं निराशा का नाम है। वह इस संघर्ष को जीवन का एक अंश तथा आवश्यक अंग समझते थे। मानव की उच्चता तथा मनुष्यत्व को सब कुछ मानकर उसके भावों तथा विचारों का वर्णन करने में वह अत्यन्त निपुण थे और यह वर्णनशैली ऐसे नए ढंग की है कि इसे पढ़कर शताब्दियों बाद भी पाठक मुग्ध हो जाता है। मिर्ज़ा का जीवन अनेक विलक्षणताओं एवं विशेताओं का समवाय था। उनके विषय में पहली बात तो यह है कि वह अत्यन्त शिष्ट, शालीन एवं मिजरेमी थे। जो कोई उनसे मिलने आता, उससे खुले दिल से मिलते थे। इसीलिए जो आदमी एक बार इनसे मिलता था, उसे बराज इनसे मिलने की इच्छा बनी रहती थी। मित्रों के प्रति अत्यन्त वफ़ादार थे। उनकी खुशी में खुशी, उनके दु:ख में दु:खी। मित्रों को देखकर बाग़-बाग़ हो जाते थे। उनके मित्रों का बहुत बड़ा दायरा था। उसमें हर जाति, धर्म और प्रान्त के लोग थे। वैसे वे शिया मुसलमान थे, पर मज़हब की भावनाओं में बहुत उदार और स्वतंत्र चेता थे। गालिब सदा किराये के मकानों में रहे, अपना मकान न बनवा सके। ऐसा मकान उनको पसंद करते थे, जिसमें बैठकखाना जरूर हो और उनके दरवाज़े भी अलग हों, जिससे यार-दोस्त बेझिझक आ-जा सकें। खाने-खिलाने के शौक़ीन, स्वादिष्ट व्यंजनों के प्रेमी थे। उन्हें हम स्नेह एवं मित्रता की छांह देने वाले बरगद कहे तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। हर जुआ का वो आसरा...उसके दिल में धड़कता था आगरा... उनका जन्म आगरा में 27 दिसंबर 1797 को एक सैनिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ था। उनका पूरा बचपन ताजनगरी में ही बीता। गालिब की पृष्ठभूमि एक तुर्क परिवार से थी और इनके दादा मिर्जा कोबान बेग खान मध्य एशिया के समरकन्द से सन् 1750 के आसपास अहमद शाह के शासन काल में भारत आये। उन्होंने दिल्ली, लाहौर व जयपुर में काम किया और अन्ततः आगरा में बस गये। जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही वह दिल्ली चले आए। यहां जाने के बाद भी तादम्र मिर्जा गालिब के दिल व दिमाग में आगरा छाया रहा। आगरा गालिब के जन्मस्थान को इन्द्रभान कन्या अन्तर महाविद्यालय में बदल दिया गया है, जिस कमरे में गालिब का जन्म हुआ था उसे आज भी सुरक्षित रखा गया है। दिल्ली के चांदनी चौक के बल्लीमारान इलाके के कासिम जान गली में स्थित गालिब के घर को गालिब मेमोरियल में तब्दील कर दिया गया। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने 1850 ई. में गालिब को दबीर-उल-मुल्क और नज्म-उद-दौला की उपाधि प्रदान की थी। इसके अलावा बहादुर शाह जफर द्वितीय ने गालिब को मिर्जा नोशा की उपाधि प्रदान की थी, जिसके बाद गालिब के नाम के साथ मिर्जा शब्द जुड़ गया। तबियत से खुद एक शायर बहादुर शाह जफर द्वितीय ने कविता सीखने के उद्देश्य से 1854 में गालिब को अपना शिक्षक नियुक्त किया था। बाद में बहादुर शाह जफर ने गालिब को अपने बड़े बेटे शहजादा फखरूद्दीन मिर्जा का भी शिक्षक नियुक्त किया था। इसके अलावा गालिब मुगल दरबार में शाही इतिहासविद के रूप में भी काम करते थे। साल 1847 में जुआ खेलने के जुर्म में गालिब को जेल भी जाना पड़ा था और उन्हें 200 रूपए जुर्माना और सख्रम कारावास की सजा दी गई थी। एक मुसलमान होने के बावजूद गालिब ने कभी रोजा नहीं रखा। मुसलमान होने के प्रश्न पर एक अंग्रेज कर्नल को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं आधा मुसलमान हूं। ये जवाब सुनकर अंग्रेज कर्नल ने अगला सवाल दागा और पूछा कि ऐसा कैसे कि आप आधे मुसलमान हैं? इसके जवाब में मिर्जा गालिब ने कहा, हां, क्योंकि मैं शराब तो पीता हूं लेकिन सुअर नहीं खाता। मिर्जा गालिब का यह जवाब सुनकर अंग्रेज कर्नल अपनी हंसी नहीं रोक पाया। एक बार गालिब आम खा रहे थे। जमीन पर छिलके जमा कर रखे थे। वहां खड़े एक व्यक्ति ने उन छिलकों को अपने गधे को खाने के लिए दिया। गधे ने उन छिलकों को खाने से इंकार कर दिया। इस पर सज्जन व्यक्ति ने गालिब का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 'गधे भी आम नहीं खाते हैं।' इस पर गालिब ने अपनी हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए कहा कि 'गधे ही आम नहीं खाते हैं।' मिर्जा गालिब का एक बहुत मशहूर शेर है 'ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिये, इक आग का दरिया है और डूबकर जाना है।' न जाने गालिब ने किन परिस्थितियों में ये शेर गढ़ा होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इश्क पर जो पहरा उस सदी में था वह आज इक्कीसवीं सदी के ग्लोबल इंडिया में भी है। जिंदगी जीने के तमाम तरीके भले ही बदल गए हों, लेकिन प्यार मोहब्बत को देखने का हमारा पारिवारिक-सामाजिक-धार्मिक नजरिया आज भी सदियों पुराना है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विधि तरीके को पूरा करोगे तब आप यह समझना चाहते है कि आपके नीचत के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जब आपके सितारे बुलंद होंगे और दूसरे तरफ, आपकी किस बात से लक्ष्मजन लक्ष्मी रुकता है जिसे हमारे ज्योतिषी उपाय के और जरूरत हो तो कुछ उपाय उपाय लक्ष्मजनक उपाय यहां मालूम करेंगे, विशेष पारमर्शित तरीके से भी, जब तक लक्ष्मजनक हमें संतुष्ट और कामीन में लक्ष्म प्राप्त करेगा

मेष

आज का दिन उत्साह और प्रसन्नतापूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहने से सुख और आनंद की अनुभूति होगी। सगे-संबंधियों या मित्रों से उपहार मिलेगा। कहीं घूमने जाना और स्वादिष्ट भोजन आपके दिन को खुशहाल बनाएगा।

वृष

मित्रों से लाभ हो सकता है। किसी धार्मिक कार्य तथा धार्मिक यात्रा में व्यस्त रहेंगे। विदेश में रहने वाले परिजनों के समाचार से आनंद होगा। भाई-बंधु से लाभ होने की संभावना है। आज का दिन आर्थिक लाभ का दिन है।

मिथुन

आर्थिक योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी होंगी। विवाहोत्सुक युवक-युवतियों के विवाह की संभावना है। आपके व्यवसाय के लिए आज का दिन बहुत अच्छा और श्रेष्ठ है। अधिकारियों की आप पर कृपादृष्टि रहेगी।

कर्क

आज आपके तन और मन का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। खर्च की चिंता से मन अशांत रह सकता है। वाणी पर संयम रखना आत अावश्यक है। कार्यालय में सहकर्मियों से आपको लाभ होगा। मन में नेगेटिव विचार आने से नुकसान हो सकता है। आज लोगों पर इंप्रेशन जमा पाएंगे।

सिंह

आज आप नए काम की शुरुआत ना ही करें। भाषा और व्यवहार पर संयम रखने से आपको लाभ होगा। सबंधत का ध्यान रखें। ज्योतिष विद्या और धार्मिक काम आपको आकर्षित करेंगे। आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए समय अच्छा है।

कन्या

नौकरी और व्यवसाय में अनुकूल परिस्थितियां होंगी। धन लाभ होने की संभावना है। विशेष कर महिला मित्रों से लाभ होगा। दोस्तों के साथ भ्रमास तथा पर्यटन पर जा सकते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ अच्छा समय गुजारेंगे। भाग्य आपके साथ है।

तुला

आपको वित्तीय लाभ हो सकता है। सहकर्मी और सेवकों से सहायता मिलेगी। सभी काम में सफलता और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे। जो लोग कला और साहित्य में रुचि रखते हैं, वे अपनी प्रतिभा अच्छी तरह प्रदर्शित कर सकेंगे।

वृश्चिक

आज आपका दिन कुछ अलग तरीके से गुजरेगा। खुद के लिए आप समय निकाल सकेंगे। दोस्तों के साथ घूमना-फिरना, मौज-मस्ती, मनोरंजन, पर्यटन तथा भोजन आदि से आप बहुत आनंदित रहेंगे। मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

धनु

आज आपको अपने वाणी और व्यवहार में सावधानी रखने की जरूरत है। आपकी बातचीत से कोई गलतफहमी न हो, उसका ध्यान रखें। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और विशेषकर आंखों में तकलीफ हो सकती है।

मकर

आज खर्च का दिन है। मानसिक चिंता बनी रहेगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचें। ईश्वर की भक्ति और आध्यात्मिक बातों में रुचि लेने से मन को कुछ शांति मिलेगी। आज का दिन आपके लिए लाभदायक साबित होगा।

कुंभ

आपकी कोई प्रशंसा कर सकता है। आप किसी बात को लेकर सम्मानित महसूस करेंगे। वाहन सुख प्राप्त होगा। प्रियजन से मुलाकात होगी। मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा और लाभदायक लग रहा है।

मीन

पिता की ओर से लाभ के संकेत है। सरकारी कामों में लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गृहस्थजीवन मधुरतापूर्ण रहेगा। जमीन, मकान एवं संपत्ति के सौदे सफल रहेंगे। सगे-संबंधियों के साथ यात्रा का आयोजन हो सकता है। जमीन, मकान एवं संपत्ति के सौदे सफल रहेंगे।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार साथियों हमारे आज के शख्सियत कॉलम के स्टार हैं। ब्यावर जिले के पुलिस कप्तान श्री श्याम सिंह (आईपीएस) बेहद मजबूत अधिकारियों के रूप में श्याम सिंह जी को जाना जाता है। जहां भी रहे वहां पूरी मजबूती के साथ पुलिस के इकबाल को बुलंद किया। 4 अगस्त सन 1965 को नागौर जिले में जन्में श्याम सिंह पुलिस में बतौर आरपीएस भर्ती हुए और अनेक स्थानों पर सीओ रहे और इसके बाद प्रमोट होकर कई जिलों में एडिशनल एसपी लगाए गए। जहां रहकर उन्होंने कई बड़ी वारदात के खुलासे किए। 22 जनवरी 2020 भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति हुए और आज पुलिस अधीक्षक, ब्यावर पद को सुशोभित कर रहे हैं। इससे पूर्व पुलिस उपायुक्त मुख्यालय पुलिस आयुक्तालय, जयपुर। पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर।

पुलिस अधीक्षक, जालोर(दूसरी बार)। पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा। पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू। पुलिस अधीक्षक, कमाण्डेन्ट, 14वी बटालियन, आरएसी पहाड़ी, भरतपुर। पुलिस अधीक्षक, जालोर। पुलिस अधीक्षक, सीआईडी सी.बी जयपुर रहे। बेहद मजबूत पुलिस अधिकारी के रूप में इनका नाम शुमार है। जहां भी रहे पुलिस के इकबाल को बुलंद किया। अलवर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर रहते हुए इनकी

श्री श्याम सिंह (आईपीएस) एसपी ब्यावर

शानदार कार्रशैली को बड़े करीब से देखा। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

27 दिसंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- स्टीम इंजन वाले पहले पब्लिक रेलवे का निर्माण 1825 में इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच पूरा हुआ।
- कलकत्ता (अब कोलकाता) में 1861 में पहली बार चाय की सार्वजनिक बोली संपन्न।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता (अब कोलकाता) अधिवेशन के दौरान 1911 में पहली बार 'जन गण मन' गाया गया।
- टोक्यो में 1923 में जापान के युवराज एक हत्या के प्रयास में सुरक्षित बच गए।
- पर्सिया के शाह ने 1934 में पर्सिया का नाम बदलकर ईरान करने की घोषणा की।
- तुर्की में 1939 में आये भूकंप से लगभग चालीस हजार लोगों की मौत।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान करने के लिए 1945 में विश्व बैंक की स्थापना की गई।
- 29 सदस्य देशों के साथ 1945 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना।
- नीदरलैंड ने 1949 में आधिकारिक रूप से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया।
- द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 1945 में मास्को के एतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जिसके आधार पर कोरिया प्रायद्वीप जो एक देश समझा जाता था दो भागों में विभाजित हो गया।
- फ्रांस ने 1960 में परमाणु परीक्षण किया।
- बेल्जियम और कांगो के बीच 1961 में राजनयिक संबंध बहाल हुए।
- दुनिया की सबसे लंबी गुफा 'केव ऑफ स्वैलोज' की खोज 1966 में एक्सिमोन, मैक्सिको में की गई।
- चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला मानव मिशन अपोलो-8 1968 में प्रशांत महासागर में उतरा।
- उत्तरी कोरिया में 1972 में नया संविधान प्रभाव में आया।
- झारखंड के धनबाद जिले स्थित चासनाला में 1975 में हुए कोयला खदान दुर्घटना में 372 लोगों की मौत।
- अफ़ग़ानिस्तान ने 1979 में राजनीतिक परिवर्तन एवं हफीजुल्लाह अमीन की सैनिक क्रान्ति में हत्या।
- यूरोप के विपना और रोम हवाई अड्डों पर 1985 में चरमपंथियों के हमले में 16 लोग मारे गए और सौ से ज्यादा घायल हुए।
- आस्ट्रेलिया में 2000 में विवाह पूर्व संबंधों को क़ानूनी मान्यता।
- भारत-पाक युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस सक्रिय; लश्कर-ए-तोइबा ने 2001 में अब्दुल वाहिद कश्मीरी को अपना नया प्रमुख नियुक्त किया।
- संयुक्त राष्ट्र ने 2001 में पाक आतंकवादी संगठन 'उम्मा-ए-तामीर ए ओ' के खाते सील करने के आदेश दिये।
- 'इंव' नामक पहले मानव क्लोन ने 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लिया।
- भारत ने 2004 में तीसरे और अन्तिम वनडे में बांग्लादेश को हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती।
- सन 2007 में रावलपिंडी के पास पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की गोली मारकर हत्या।
- सन 2008 में वी. शान्ताराम पुरस्कार समारोह में तारे जमीं पर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला।

27 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति

- जर्मनी के गणितज्ञ और खगोलशास्त्री यूहान केपलर का जन्म 1571 में हुआ।
- उर्दू-फ़ारसी के प्रख्यात कवि मिर्जा गालिब का जन्म 1797 में हुआ।
- पंजाब के प्रमुख सिक्ख कार्यकर्ता ऊज्जवल सिंह का जन्म 1895 में हुआ।
- उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी का जन्म 927 में हुआ।
- भारत के राजनेता तथा हिन्दी साहित्यकार शंकर दयाल सिंह का जन्म 1937 में हुआ।

विशेष आलेख

हरी कथा और श्री हरि के दर्शन

आज मैं काफी खुश था क्योंकि अलवर के एक सतसंग भवन में एक कथा वाचक आने वाले थे। खुश इसलिए था कि उन कथा वाचक का काफी नाम सुना था। लोग उन्हें भगवान की संज्ञा देते थे। बात उस समय की है जब मैं फोटोग्राफी की पहली सीढ़ी पर ही चढ़ा था। ज्ञान से परे था इसलिए भक्ति का पूरा महत्व समझता था। खैर कैमरा लेकर मन्दिर के (सतसंग भवन)बाहर ही खड़ा था। आयोजक ने पहले की कह दिया था कि आते समय आचार्य की आरती के समय का मेरा फोटो जरूर ले लेना सो मैं पूरी तरह तैयार था। एक आदमी बाईक पर आया उसके हाथ में झंडा था आते ही उसने आस पास से साईकिल और स्कूटर्स हटाएए और खड़ा हो गया। आयोजक भी पूरी तरह तैयार थे आरती का थाल हाथ में लेकर। मालूम पैन मैं महाराज आए उस समय मारूति वैन ही फॉचूनर के बराबर ही थी। ऐसा लगा कि स्वयं भगवान प्रगट हो गए हों। श्वेत वस्त्र,एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ मे जल का कमण्डल,बगल में माला का स्टैंड, खुले अर्ध श्याम-अर्ध श्वेत केश,मस्तक पर सिंदूर और गोपी वंदन का मिक्स तिलक,आँखों में ओजस का भाव,मस्तक प्रकाशवान पर्वत की तरह सुशोभित, बैठे जैसे मां नारायणी स्वयं सरंक्षण कर रही हो। डीले डौल लम्बा चौड़ा,पाँवो में पूरी तहर एक खण्ड वाली लकड़ी की खडाऊ। मेरा ध्यान सिर्फ फोटो में ही नहीं था मैं फोटो के साथ साथ बुपवाद से भगवान के दर्शन भी कर रहा था। खैर आरती के बाद जैसे ही कथावाचक आचार्य भीतर आए जयश्री राम के उद्घोष और गुलाब के फूलों की पतियों की बारिश का अद्भुत और आलौकिक नजारे को स्वर्ग जैसा बना दिया खैर आचार्य जी सतसंग भवन के उपर बने एक शानदार कमरे में ठहराया गया। कमरे मे सिर्फ आयोजक मंडल से जुडे हुए लोगों के अलावा मैं ही था जिसे जाने की अनुमति थी। मैं सोच रहा था कि महाराज श्री के पाँव तो एक बार छूं लूं तो बेड़ा पार हो जाए, मौका मिला फोटो वगैहरा खीचने के बाद मेंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए भीड़ में जैसे तैसे पाँव छू ही लिए। कल सुबह से प्रवचन होने थे इसलिए अब महाराज को विश्राम की जरूरत थी सो कैमरे में उनके दो सेवादार रूक गए बाकि सभी बाहर आ गए। मुझे कहां चैन था आयोजक ने कहा कि शाम को महाराज श्री मन्दिर में आरती करेंगे तो देख लेना यदि फोटो ले तो। नेकी और पुछ-पुछ. शाम होने में सिर्फ दो घण्टे थे सो घर नहीं गया, शाम तक मैं वहीं रूका रहा भोजन प्रसादी मन्दिर में ही ले लिया। आरती की पूरी तैयारी हो गई थी बस सब आचार्य जी का इंतजार कर रहे थे। महाराज आए ऐसे डैकोरस से ऐसा लगा कि साक्षात विष्णु महादेव की महाआरती कर रहे हो। सच कहू तो मेरा ध्यान आरती में कम आचार्य के हाव भाव में ज्यादा लगा हुआ था। आरती के बाद प्रसाद वितरित हुआ महाराज थोड़ी देर के लिए राम जी की बातें बताने लगे थे। सबको बड़ा आनन्द आ रहा था। मैं भी उन आनन्द लेने वालो मे से एक था। बड़ा ही आनन्द आ रहा था। उनकी आलौकिक वाणी,काम,क्रोध,लोभ,मोह और अहंकार तो ऐसे मानों उनके इंदीगर्द भी नजर नहीं आ रहे थे। बिल्कुल सरल,सरस और सौम्य वाणी के धनी आचार्य ने सबका मन मोह लिया। खैर दूसरे दिन सतसंग कथा का शुभारंभ था। मैं सबसे आगे था विडियों कैमरा ट्राईपोड पर लगाकर पूरी तरह तैयार था। महाराज आए व्यास गद्दी का पूजन हुआ और कथा वाचन शुरू हुआ। कथा के लिए महाराज खुद हारमोनियम लेकर बैठे दायीं ओर ढोलक और बायीं ओर वायलिन वावक बैठे हुए थे। कथा से पहले महाराज ने वाईलिन वावक के साथ सामंजस्य बैठाया। कथा में

अग्रमी पंक्ति में महिलाए बैठी हुई थी आधी सी बुजुर्ग और बाकि अधेड़। महाराज ने अपनी ओजस्वी वाणी से सबको मंत्र मुग्ध कर डाला। वायलिन के सुर महिलाओं के आँखों के बहते हुई अश्रुधारा का सबसे बड़ा कारण नजर आ रही थी। महाराज बीचे-बीच में वायलिन वावक को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वह भी मुस्कुरा रहा था, मैं उन दोनों को देख कर फ्री में मुस्कुरा रहा था क्योंकि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं मुस्कुरा कर उनकी हां में हां मिला रहा था बस। कथा समाप्त होने के बाद महाराज एक सेलेब्रिटी के रूप में नजर आने लगे जो देखे वही उनके पैरो में गिर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों धरती पर भगवान स्वयं अवतरित हो गए हों। खैर मैं दूसरे दिन की कथा के दौरान मैं अपने स्थान पर पहुँच गया। महाराज श्री साज गाज वाले आ चुके थे बस महाराज के आने का इंतजार हो रहा था। महाराज आत दूसरी भेषभूषा में आए। गद्दी की आरती के बाद कथा का वावन शुरू हुआ ही था कि अचानक वायलिन का एक तार टूट गया। कथा के दौरान गंभीर और भक्ति के मनोभाव को सुर के रूप में परोसने का काम वायलिन का ही होता है। कथा वावक ने कहा कि यदि तीक नहीं हो रही है तो अपनी दूसरी वायलिन ले लो पर जल्दी करो,विलम्ब हो रहा है। वायलिन वावक ने कथा वावक महाराज श्री की बातों को अनसुना सा करके उसे ही ठीक करने की जुगत लगाना शुरू कर दिया। महाराज ने दो चार मिनट के बाद सरल भाव में दूबारा कहा कि दूसरी ले आओ। तो कथा वावक ने कहा कि दूसरी भी खराब है महाराज। बस इतना सा सुनना था कि महाराज की भौहे तन गई जिनका संरक्षण मां नारायणी कर रही थी। अँखे इतनी बड़ी हो गई मानों उनमें रक्त निकल आएगा और गुस्से से उस वायलिन वावक को भलाबुरा कहने लगे। कथा तो शुरू कर दी लेकिन बिना वायलिन के मजा ही नहीं आ रहा था। ना उन श्रृद्धालु महिलाओं को ना ही कथा वावक को क्योंकि बदलते समय के बलते भगवान के दर्शन माडीटेन के जरीए होने लगे थे सो वायलिन के तार के टूटते ही भगवान भी काफूर हो गए। पर मैं उस कथा वावक के उस बदलते स्वरूप को देख रहा था जिसने काम,क्रोध,लोभ मोह और अहंकार पर विजय पा लेने की बात एक दिन पहले ही कथा के दौरान श्रृद्धालुओं को कही थी। मुझे मैं बड़ा ऊजीब लगा कि इस संत को मैं भगवान के स्वरूप में देख रहा था। पर फिर अपने आपको समझाया कि यार जमाना भी ऐसा ही है जो दिखता है वही बिकता है तू क्यों खाली पीली मे टैन्ड़ ले रहा है.....

रूपक शर्मा
संपादकीय प्रभारी, बढ़ता राजस्थान

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इण्डस्ट्रियल रोड़ खातीपुरा,जयपुर से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-नन्दजी पठान*। प्रधान संपादक-तेज बिलास विजयवर्गीय फो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन न.01432-244481 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार